सच बोलने की हिम्मत

राजधानी चौपाल

RNI No. HARHIN/25/A3341

राजधानी चौपाल
समाचार पत्र में किसी भी प्रकार के समाचार, विज्ञप्ति और विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें...
94169-26329
93068-13001

अंक : 06 | वर्ष : 01 | साप्ताहिक (08 से 14 फरवरी 2026) | पृष्ठ 8 | मूल्य : 5/- रुपये | E-mail : rajdhanichoupal@gmail.com

सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में उठाई आवाज; सुदामा प्रसाद और आगा सैयद रहुल्लाह ने भी दिया समर्थन

मरुधरा की पुकार अब देश की संसद में : बीकानेर का 'खेजड़ी आंदोलन' बना देश का राष्ट्रीय मुद्दा

- चंद्रशेखर आजादः खेजड़ी राजस्थान की जीवनरेखा है, इसकी कटाई तुरंत रुके।
- सुदामा प्रसाद और आगा सैयदः पारंपरिक वृक्षों की रक्षा करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी।
- आंदोलन की जीतः स्थानीय संघर्ष को मिला देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच।

नई दिल्ली/बीकानेर (राजधानी चौपाल) | राजस्थान के बीकानेर में खेजड़ी पेड़ों की कटाई के विरोध में चल रहे जनआंदोलन की गूंज अब देश की संसद तक पहुंच चुकी है। गुरुवार को लोकसभा में नगीना (उत्तर प्रदेश) से सांसद श्री चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाते हुए खेजड़ी पेड़ों के संरक्षण की मांग की। उन्होंने कहा कि खेजड़ी केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि राजस्थान की संस्कृति, पर्यावरण और जीव-जंतुओं की जीवनरेखा है।

सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में कहा कि बीकानेर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खेजड़ी के पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिससे पर्यावरण संतुलन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर खेजड़ी संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की।

इस दौरान बिहार से सांसद श्री सुदामा प्रसाद तथा जम्मू-कश्मीर से सांसद श्री आगा सैयद रहुल्लाह मेहदी ने भी इस मुद्दे पर समर्थन जताया। तीनों सांसदों ने एक स्वर में कहा कि खेजड़ी जैसे पारंपरिक और पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्षों की रक्षा करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

सांसदों ने यह भी उल्लेख किया कि बीकानेर में स्थानीय लोग, पर्यावरण प्रेमी और सामाजिक संगठन लंबे समय से इस आंदोलन के माध्यम से खेजड़ी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस संघर्ष को अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने लगी है, जो आंदोलनकारियों के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि खेजड़ी का पेड़ मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, पशुओं के चारे, छाया और जैव विविधता के संरक्षण में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में इसकी अंधाधुंध कटाई भविष्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। लोकसभा में इस मुद्दे के उठने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस मामले में सकारात्मक पहल करेगी और बीकानेर सहित पूरे राजस्थान में खेजड़ी संरक्षण को लेकर प्रभावी नीति बनाई जाएगी।

बीकानेर में चल रहा यह आंदोलन अब केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की राष्ट्रीय मुहिम का रूप लेता नजर आ रहा है।

अनुभव और युवाशक्ति का संगम

परसराम – रामसिंह परिवार ने खेजड़ी आंदोलन को दी नई जान

नई दिल्ली/बीकानेर (राजधानी चौपाल) | यह समाज के लिए केवल गर्व का ही नहीं, बल्कि आत्ममंथन का भी क्षण है। खेजड़ी बचाओ आंदोलन के बीच समाज को दो ऐसे योद्धा मिले हैं, जिन्होंने अपने-अपने स्तर पर संघर्ष, साहस और प्रतिबद्धता की मिसाल पेश की है। एक ओर वरिष्ठ का तपता हुआ अनुभव है, तो दूसरी ओर युवा की ऊर्जा और स्पष्ट दिशा—और यही संगम आज आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है।

श्री परसराम जी ने हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखते हुए समाज और प्रकृति के पक्ष में मजबूती से खड़े रहकर यह साबित किया कि नई पीढ़ी भी सिद्धांतों के मामले में किसी से कम नहीं है। दबाव, डर और समझौते के दौर में भी उनकी अडिग सोच ने आंदोलन को न केवल जीवित रखा, बल्कि उसे नई गति और मजबूती दी है।

इसी दृढ़ता के कारण रामसिंह जी का परिवार आज पूरे मारवाड़ में सिरमौर कहलाने योग्य बन गया है। यह केवल एक परिवार की बात नहीं, बल्कि उस सोच की मिसाल है जो समाज को दिशा देती है। जब चारों ओर स्वार्थ हावी हो, तब भी अपने मूल्यों पर डटे रहना आसान नहीं होता—लेकिन इस परिवार ने यह कर दिखाया।

यह निर्विवाद है कि यदि परसराम जी की जगह सुभाष जी के साथ कोई और होता, तो संभव है खेजड़ी बचाओ आंदोलन अब तक कमजोर पड़ चुका होता। परंतु उनकी स्पष्ट सोच, निरंतर सक्रियता और निस्वार्थ भावना ने इस आंदोलन को नई शक्ति दी है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि आंदोलन व्यक्ति से नहीं, विचार से चलता है—और विचार तभी मजबूत होता है जब उसके पीछे समर्पित लोग खड़े हों।

आज समाज को ऐसे योद्धाओं से केवल प्रेरणा लेने की ही नहीं, बल्कि उनसे सीखने की भी आवश्यकता है। क्योंकि जब वरिष्ठों का अनुभव और युवाओं का साहस एक साथ खड़ा हो जाता है, तब कोई भी आंदोलन, कोई भी संघर्ष आसानी से दबाया नहीं जा सकता।

'राजधानी चौपाल' की पड़ताल में खुली सरकारी दावों की पोल; हेडमास्टर के पद रिक्त होने से पढ़ाई और अनुशासन दोनों ठप, निजी स्कूलों की ओर बढ़ रहे कदम

आदमपुर के 12 स्कूलों में 'अंधेर नगरी' : बिना मुखिया के कैसे संवरेगा नौनिहालों का भविष्य?

आदमपुर (राजधानी चौपाल) | सरकार भले ही सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने और शिक्षा स्तर सुधारने के बड़े दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत आदमपुर खंड के गांवों में कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। यहां 12 राजकीय हाई स्कूल ऐसे हैं जो महीनों से बिना हेडमास्टर के संचालित हो रहे हैं। परिणामस्वरूप स्कूलों में न तो अनुशासन दिखता है और न ही शैक्षणिक गुणवत्ता।

गांवों के इन स्कूलों में पढ़ाई का जिम्मा ऐसे शिक्षकों पर है, जो पहले से ही अपने विषय के कार्यभार में दबे हैं। ऊपर से उन्हें प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ रही हैं। स्थिति यह है कि कई जगह शौचालयों की सफाई तक नियमित नहीं, खेलकूद गतिविधियां ठप हैं और बच्चों की मूलभूत सुविधाएं भी प्रभावित हो रही हैं।

सूत्रों के अनुसार, आदमपुर खंड के कुल 12 राजकीय हाई स्कूलों में हेडमास्टर के पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। नियमों के तहत ऐसी स्थिति में किसी वरिष्ठ शिक्षक को डीडीओ (ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर) का अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है, लेकिन इससे स्कूल प्रबंधन और पढ़ाई दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

अभिभावकों का कहना है कि जब स्कूल में स्थायी मुखिया ही नहीं होगा, तो व्यवस्था कैसे सुधरेगी? कई स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 100 से भी कम रह गई है, क्योंकि लोग अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में करवाने लगे हैं।

बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं, रैलियां और जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन जब स्कूलों की बुनियादी व्यवस्था ही कमजोर हो, तो ऐसे प्रयास सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाते हैं।

राजधानी चौपाल सवाल उठाता है...

जब शिक्षा ही गांव की रीढ़ है, तो इन स्कूलों में स्थायी हेडमास्टर की नियुक्ति कब होगी? क्या विभाग इस गंभीर स्थिति पर संज्ञान लेकर जल्द समाधान करेगा, या गांव के बच्चों का भविष्य यूं ही लटकता रहेगा?

इन स्कूलों में हेडमास्टर के पद रिक्त हैं

- राजकीय उच्च विद्यालय, खेमपुर
- राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, खेमपुर
- राजकीय उच्च विद्यालय, भोडिया बिश्नोईयान
- राजकीय उच्च विद्यालय, बाली सतलुज
- राजकीय उच्च विद्यालय, किशनगढ़
- राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, ढ़ाबा बरवाला
- राजकीय उच्च विद्यालय, काबरेल
- राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, कोहली
- राजकीय उच्च विद्यालय, बाला
- राजकीय उच्च विद्यालय, चौहड़वाली
- राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, सीसवाल
- राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, चुहली बागड़िया

हरियाणा में 10वीं- 12वीं की परीक्षा 25 फरवरी से

भिवानी| हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षाएं 25 फरवरी से आयोजित करवाई जाएंगी। इन परीक्षाओं के संचालन के लिए सभी राजकीय व अराजकीय विद्यालयों के अध्यापक, प्राध्यापक व प्रधानाचार्य की परीक्षाओं में ड्यूटियां लगाई जानी है। बोर्ड सचिव मुनीश शर्मा ने बताया कि सभी राजकीय व अराजकीय विद्यालयों के मुखिया उन द्वारा पूर्व में भेजी गई स्टाफ स्टेटमेंट में 9 से 11 फरवरी, तक अपडेट करना सुनिश्चित करें, ताकि परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्र पर लगाई जाने वाली परीक्षा ड्यूटी में होने वाली परेशानी/समस्या से बचा जा सके। स्टाफ स्टेटमेंट अपडेट करने के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर लिंक 9 फरवरी से उपलब्ध होगा। सभी विद्यालय समय रहते स्टाफ स्टेटमेंट का डाटा संशोधित/अपडेट करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि पूर्व में राजकीय व अराजकीय विद्यालयों द्वारा जो स्टाफ स्टेटमेंट भरी गई थी, यदि विद्यालय में कार्यरत किसी अध्यापक, प्राध्यापक व प्रधानाचार्य के विवरणों में जैसे- किसी प्रकार के अवकाश या रिटायर अथवा स्थानांतरण, मोबाइल नंबर में कोई संशोधन है या अन्य कोई कारण है तो उसे भी बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर समय रहते अपडेट करना सुनिश्चित करें।

आदमपुर का लाल, देश का मान

आईपीएस मुरलीधर शर्मा को राष्ट्रपति पुलिस पदक, इलाके में जश्न

आदमपुर (राजधानी चौपाल) | मंडी आदमपुर की मिट्टी से निकले एक होनहार सपूत ने पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी मुरलीधर शर्मा को उनकी उत्कृष्ट, निष्ठावान और प्रभावशाली सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वे पश्चिम बंगाल के बैरकपुर पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात हैं।

यह पहला मौका नहीं है जब आईपीएस शर्मा की सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया हो। इससे पहले वर्ष 2019 में उन्हें मुख्यमंत्री पुलिस पदक भी मिल चुका है। राष्ट्रपति पदक मिलते ही आदमपुर समेत पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है।

हरियाणा का गौरव, देश का सम्मान

आईपीएस मुरलीधर शर्मा को मिला राष्ट्रपति पुलिस पदक न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह आदमपुर, हरियाणा और पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। राजधानी चौपाल की ओर से इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाई-सचमुच, आदमपुर का लाल आज देश का सम्मान बन गया है।

सरकारी स्कूल से राष्ट्रपति सम्मान तक का सफर

आईपीएस मुरलीधर शर्मा की कहानी मेहनत, लगन और संकल्प की मिसाल है। उन्होंने आदमपुर के सरकारी स्कूल से 10वीं पास की, फिर फिरोज गांधी मैमोरियल राजकीय महाविद्यालय से बीए, पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए और जेएनयू से राजनीति विज्ञान में एमफिल की पढ़ाई पूरी की। साल 2004 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास कर वे पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस अधिकारी बने।

बीरभूम से कोलकाता तक दमदार सेवाएं : अपने करियर की शुरुआत उन्होंने बीरभूम जिले के एसपी के रूप में की। इसके बाद कोलकाता में डीसीपी (साउथ), स्पेशल टास्क फोर्स सहित कई अहम और चुनौतीपूर्ण पदों पर रहते हुए कानून-व्यवस्था को मजबूती दी। उनकी पहचान एक सख्त, ईमानदार और संवेदनशील अधिकारी के रूप में रही है।

वर्दी के साथ कलम और कला का संगम : आईपीएस मुरलीधर शर्मा सिर्फ एक कड़क अफसर ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील साहित्यकार भी हैं। साहित्य जगत में वे 'तालिब' के नाम से जाने जाते हैं। उनकी शायरी और गजलें उर्दू पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी पहली किताब प्रकाशित हो चुकी है और दूसरी किताब इसी माह पाठकों के बीच आने वाली है। वे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला भाषाओं के जानकार हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों में भी उनकी गहरी रुचि रही है। स्थानीय रामलीला में राम की भूमिका, हनुमान कीर्तन मंडल और कृष्ण प्रणामी सत्संग में सक्रिय भागीदारी उनके बहुआयामी व्यक्तित्व को दर्शाती है। उनकी लिखी बंगाली फिल्म 'मृग्या–द हंट' का हिंदी गाना 'शोर मचा' सुपरहिट रहा।

शिक्षकों और क्षेत्रवासियों में गर्व :उनके इस सम्मान पर पूर्व शिक्षक डॉ. हरपाल, छोटे लाल जस्सु, डॉ. सुनील वर्मा, रामसिंह बैनीवाल, कृष्ण नूनियां समेत कई गणमान्यजनों ने हर्ष व्यक्त किया। सभी ने इसे आदमपुर और हरियाणा के लिए गौरव का क्षण बताया।

कांग्रेस ने दावेदारों से पूछा- आपके खिलाफ कोई मामला दर्ज तो नहीं

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| राज्य में तीन नगर निगमों समेत सात निकायों के होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस की चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं से आवेदन का गुरुवार आखिरी दिन है। सभी जिलाध्यक्षों को आवेदन जमा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खास बात यह है कि आवेदन के लिए एक निर्धारित प्रफोर्मा बनाया गया है। जिसमें सामान्य जानकारी के साथ यह भी पूछा गया कि उसके खिलाफ कोई एफआईआर तो नहीं है। यदि है तो उसकी जानकारी भी दें। इसी प्रकार यह भी बताना होगा कि किसी मामले में दो साल से अधिक समय की सजा हुई है या नहीं। यानी कांग्रेस इस आवेदन प्रफोर्मा के जरिए उम्मीदवार का क्राइम रिकॉर्ड पर भी नजर रखे हुए है। ताकि बाद में कोई उंगली न उठाए।

गुरुवार तक आवेदन जमा होने के बाद नगर निगम स्तर पर बनी कमेटियों इनकी स्क्रूटनी करेंगी और पैनल गठित चुनाव समिति में रखा जाएगा। इस कमेटी में ही नाम तय होंगे। इसके लिए प्रभारी व दिल्ली नेतृत्व से भी चर्चा की जा सकती है। अभी तीनों सोनीपत, अम्बाला और पंचकूला में भाजपा के मेयर थे। पंचकूला तो पिछला चुनाव करीब दो हजार वोटों से ही हारी थी। अब कांग्रेस का संगठन भी बन चुका है। ऐसे में कांग्रेस विधानसभा चुनाव के हो रहे इन पहले चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतर रही है।

हिसार में जल निकासी परियोजना का शिलान्यास : कैबिनेट मंत्री गंगवा बोले- 13.91 करोड़ आएगी लागत, मिलगेट व आसपास सेक्टरों में नहीं भरेगा पानी

हिसार| हिसार के मिलगेट एरिया सहित सेक्टर-1 एवं 4, सेक्टर-3 और सेक्टर 5 में जलनिवासी का स्थायी समाधान हो सकेगा। प्रदेश के जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने इसको लेकर एयरपोर्ट चौक के समीप शुक्रवार को वर्षा जल निकासी व्यवस्था सहित समस्त विकास कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया।

इस महत्वपूर्ण विकास परियोजना पर 13.91 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य केवल बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।

उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रभावी वर्षा जल निकासी व्यवस्था समय की मांग है और इन विकास कार्यों के पूरा होने के बाद हिसार के इन क्षेत्रों में चली आ रही समस्याओं का स्थायी समाधान होगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विकास कार्य उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप और निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार जनता के धन का उपयोग पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कर रही है, ताकि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में निर्णायक बजट : राव नरबीर सिंह

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| केंद्र सरकार 3.0 का प्रस्तुत किया गया यह बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का स्पष्ट रोडमैप है। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य, युवा सशक्तिकरण और वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने इस बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का "साक्षात ब्लूप्रिंट" बताते हुए कहा कि यह बजट आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार, उद्योग और ग्रामीण विकास की तस्वीर बदलने वाला है।

राव नरबीर सिंह ने कहा कि यह बजट आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने, निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। बजट में सात प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिनमें कृषि, एमएसएमई, विनिर्माण, अवसंरचना, कौशल विकास, नवाचार और सीमावर्ती/रणनीतिक क्षेत्रों का विकास शामिल है।

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती

बजट में किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक तकनीक और बाजार से जोड़ने, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इससे न केवल कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

राजधानी चौपाल का विश्लेषण

यह बजट स्पष्ट रूप से बताता है कि सरकार का फोकस केवल तात्कालिक राहत पर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाने पर है। यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो आने वाले वर्षों में भारत आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक रूप से नई ऊंचाइयों को छू सकता है। यह बजट वास्तव में भारत के भविष्य की नींव है — और हरियाणा जैसे राज्यों के लिए विकास की नई संभावनाओं का द्वार।

एमएसएमई और विनिर्माण क्षेत्र को नई ऊर्जा

एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता, आसान ऋण, और नई औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। राव नरबीर सिंह ने कहा कि इससे छोटे उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी और 'मेक इन इंडिया' अभियान को नई गति मिलेगी।

रोजगार सृजन और कौशल विकास पर फोकस

युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण, स्टार्टअप को प्रोत्साहन, और नई रोजगार योजनाओं के माध्यम से देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास इस बजट में स्पष्ट दिखता है। इससे हरियाणा जैसे औद्योगिक राज्य में रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।

अवसंरचना और रणनीतिक क्षेत्रों में विस्तार

सड़क, रेल, लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक कॉरिडोर और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए विशेष बजट प्रावधान किए गए हैं। इससे व्यापार, परिवहन और सुरक्षा – तीनों क्षेत्रों में मजबूती आएगी।

नवाचार, अनुसंधान और डिजिटल इंडिया

बजट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार को प्रोत्साहित करने पर भी विशेष बल दिया गया है, जो भारत को तकनीकी रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

राव नरबीर सिंह ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत के विज़न को साकार करने वाला है। यह न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी भारत को तैयार करता है।

बजट 2026-27 में दिखी जमीनी सोच, विकास की ठोस दिशा : रूचि कौशिक व पुरुषोत्तम कौशिक

सरकार ने ग्रामीण और शहरी विकास के बीच संतुलन बनाते हुए योजनाएं तैयार की हैं,

पुरुषोत्तम कौशिक,एडवोकेट
(अध्यक्ष खैड़की दौला मंडल, भाजपा गुरुग्राम), (सदस्य जिला कष्ट निवारण समिति, गुरुग्राम)

रूचि पुरुषोत्तम कौशिक
पार्षद, वार्ड -3, नगर निगम मानेसर, गुरुग्राम
(भाजपा पार्षद)

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| गुरुग्राम के मानेसर क्षेत्र में बजट को लेकर जनप्रतिनिधियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है। वार्ड-3 की पार्षद रूचि पुरुषोत्तम कौशिक और भाजपा के खैड़की दौला मंडल अध्यक्ष एवं एडवोकेट पुरुषोत्तम कौशिक ने कहा कि इस वर्ष का बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि जमीनी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई एक स्पष्ट विकास रूपरेखा है।

पार्षद रूचि कौशिक ने कहा कि नगर निगम क्षेत्रों के लिए बुनियादी सुविधाओं, सफाई व्यवस्था, सीवर, पानी और सड़कों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, वे सीधे तौर पर शहरी जनता के जीवन स्तर को बेहतर करेंगे। मानेसर जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र के लिए यह बजट विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किए गए प्रावधान सराहनीय हैं।

वहीं एडवोकेट पुरुषोत्तम कौशिक ने बजट को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम बताते हुए कहा कि इसमें रोजगार, उद्योग, स्टार्टअप, युवाओं और छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी राहत दी गई है। गुरुग्राम जैसे औद्योगिक जिले में इसका सीधा लाभ देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण और शहरी विकास के बीच संतुलन बनाते हुए योजनाएं तैयार की हैं, जिससे अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य के रूप में उन्हें अक्सर जनता की समस्याएं सुनने का अवसर मिलता है, और इस बजट में उन्हीं समस्याओं के समाधान की झलक साफ दिखाई देती है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल सुविधाओं पर विशेष जोर भविष्य के भारत की मजबूत नींव तैयार करेगा।

दोनों जनप्रतिनिधियों ने विश्वास जताया कि यह बजट केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि धरातल पर तेजी से क्रियान्वित होकर आम जनता को राहत देगा। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट देश और प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेगा। मानेसर और गुरुग्राम क्षेत्र की जनता को इससे प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और विकास की रफ्तार और तेज होगी।

बजट पर प्रतिक्रिया...

"किसान, श्रमिक, युवा और मध्यम वर्ग, हर वर्ग के हितों का संतुलित बजट" : पवन यादव वजीराबाद

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| भाजपा गुरुग्राम के वजीराबाद मंडल अध्यक्ष और ग्रीवेंस कमेटी सदस्य पवन यादव ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट दूरदृष्टि, संतुलन और समावेशी विकास की सोच के साथ तैयार किया गया है, ताकि समाज के हर वर्ग को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिल उन्होंने कहा कि इस केंद्रीय बजट में किसान, श्रमिक, मध्यम वर्ग, उद्योग, युवा और महिलाओंकृसभी के हितों का समुचित ध्यान रखा गया है। यह बजट न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि भविष्य की आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। पवन यादव ने कहा कि कैंसर की दवाओं और उपचार से जुड़े उपकरणों पर ड्यूटी में कटौती कर सरकार ने मानवीय संवेदनाओं का परिचय दिया है, जिससे गंभीर रोगों से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।

विकसित भारत के रोडमैप को गति देता बजट 2026-27 : अनिल सैनी

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| बजट 2026-27 को विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा और प्रभावी कदम माना जा रहा है। आर्थिक ग्रोथ को रफ्तार देने, निवेश और उद्योग को प्रोत्साहन देने तथा रोजगार सृजन को मजबूत करने पर इस बजट का स्पष्ट फोकस दिखाई देता है। 'सबका साथ, सबका विकास' की अवधारणा के अनुरूप यह बजट आम नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करता है। बेहतर सुविधाएं, नए अवसर और विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की सोच इस बजट की प्रमुख विशेषता है।

श्री राम नगर (फरुखनगर) भाजपा मंडल अध्यक्ष व हरियाणा सरकार की लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के सदस्य अनिल सैनी ने बजट का स्वागत करते हुए इसे जनता-केंद्रित और भविष्य उन्मुख बताया है।

विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता की राह पर बजट 2026-27: अरुण त्यागी

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 को विकास, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने, मध्यम वर्ग को राहत देने, किसानों को सशक्त बनाने और युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने पर विशेष फोकस इस बजट की प्रमुख विशेषता है।यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने का रोडमैप है। संतुलित और दूरदर्शी प्रावधानों के साथ यह बजट भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भाजपा गुरुग्राम के मंडल अध्यक्ष अरुण त्यागी ने बजट का स्वागत करते हुए इसे देश के हर वर्ग के लिए लाभकारी और भविष्य उन्मुख बताया है।

बजट पर टीकली मंडल की प्रतिक्रियाः विकास और जनहित को मिली प्राथमिकता

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| गुरुग्राम के टीकली मंडल के अध्यक्ष श्रवण राघव और महामंत्री योगेश चौहान ने हालिया बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे जनकल्याण और विकास को गति देने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट आम नागरिक, किसान, युवा और मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है।

श्रवण राघव ने कहा कि बजट में बुनियादी सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के अवसरों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी। वहीं योगेश चौहान ने कहा कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो प्रावधान किए हैं, वे समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाएंगे।

दोनों पदाधिकारियों ने विश्वास जताया कि इस बजट के प्रभावी क्रियान्वयन से गुरुग्राम सहित पूरे प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज होगी और आम जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

उद्योगों को मजबूती देने एवं आर्थिक विकास को गति प्रदान करने वाला है बजट : केके गांधी

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट में उद्योग जगत, एमएसएमई सेक्टर, रोजगार सृजन एवं समग्र सामाजिक विकास को संतुलित रूप से प्राथमिकता दी गई है। इस बजट की उद्योग जगत के संगठनों ने सराहना की है। उद्यमियों का प्रतिनिधित्व करने वाले इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एसोसिएशन (आईडीए) के अध्यक्ष केके गांधी ने कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उद्योगों को मजबूती देने वाला एवं आर्थिक विकास को गति प्रदान करने वाला है। देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए आम बजट में जरुरत से ज्यादा प्रावधान किए गए हैं।

सभी वर्गों के भविष्य को सशक्त बनाने के प्रति समर्पित है बजट : रवि बंसल

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| विकसित भारत का बजट देश को तेज विकास, आत्मनिर्भरता और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में आगे ले जाने वाला बजट है। यह कहना है कि भाजपा आईटी सैल के प्रदेश सह संयोजक रवि बंसल का। उनका कहना है कि यह बजट गरीब, युवा, किसान, महिला और मध्यम वर्ग सभी के सशक्त भविष्य को समर्पित है। उन्होंने बजट को विकसित भारत का बजट बताया है।

बजट पर बंटी राय

उद्योग जगत ने किया स्वागत, विपक्ष और कर्मचारी संगठनों में निराशा

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आम बजट पर देशभर में अलग-अलग वर्गों की प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। जहां उद्योग जगत, व्यापारिक संगठनों और सत्ताधारी दल के नेताओं ने इस बजट को आर्थिक गति देने वाला और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में निर्णायक कदम बताया है, वहीं कर्मचारी संगठनों, युवा वर्ग और विपक्षी दलों ने इसे आम आदमी से दूर और निराशाजनक करार दिया है।

गुरुग्राम सहित एनसीआर के व्यापारिक संगठनों में बजट को लेकर उत्साह दिखाई दिया। गुरुग्राम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) और विभिन्न औद्योगिक संगठनों ने बजट में एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल विस्तार और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर दिए गए फोकस का स्वागत किया। उनका मानना है कि इससे घरेलू उद्योग को मजबूती मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भारत वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करेगा।

उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि 2026-27 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, स्टील और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को सीधा लाभ देगा। टेक्सटाइल, फाइबर और पारंपरिक उद्योगों को नीति स्तर पर नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई गई है। कई व्यापारिक नेताओं ने इसे "विकसित भारत की दिशा में ठोस बजट" बताया।

भाजपा जिला कार्यालय गुरुग्राम में बड़ी स्क्रीन पर बजट का सीधा प्रसारण देखा गया। इसके बाद उद्यम एवं वाणिज्य से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि यह बजट भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा। लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष भी उतना ही मुखर रहा।

कांग्रेस के जिला अध्यक्ष (शहरी) पंकज डावर ने बजट को "ट्रिपल इंजन सरकार की विफलता" बताते हुए कहा कि हरियाणा जैसे औद्योगिक राज्य के लिए कोई विशेष राहत या घोषणा नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी-बड़ी बातों के बावजूद बजट में आम नागरिक और मध्यम वर्ग के लिए ठोस राहत नहीं है।

कर्मचारी संगठनों और पेंशन बहाली संघर्ष समितियों ने भी बजट पर निराशा जताई। उनका कहना है कि न तो पुरानी पेंशन योजना (OPS) पर कोई स्पष्टता दी गई, न ही वेतन आयोग या कर्मचारियों के हित में कोई ठोस घोषणा की गई। युवा वर्ग के लिए रोजगार सृजन के स्पष्ट रोडमैप की कमी भी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी।

गुरुग्राम के कर्मचारी नेताओं का कहना है कि बजट में उद्योग और पूंजी निवेश पर फोकस तो है, लेकिन नौकरीपेशा, पेंशनभोगी और निम्न आय वर्ग के लिए ठोस राहत नहीं दिखाई देती। यही कारण है कि कर्मचारी संगठनों में बजट को लेकर असंतोष का माहौल है। स्पष्ट है कि यह बजट आर्थिक दृष्टि से उद्योग जगत के लिए उम्मीदें लेकर आया है, लेकिन सामाजिक और रोजगार के मोर्चे पर कई सवाल भी खड़े कर गया है।

राजधानी चौपाल की पड़ताल में सामने आया कि गुरुग्राम जैसे औद्योगिक शहर में भी बजट को लेकर राय दो हिस्सों में बंटी हुई है—एक ओर विकास और निवेश की उम्मीद, दूसरी ओर रोजगार, पेंशन और आम आदमी की राहत को लेकर चिंता।

आखिरकार, बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होता, बल्कि जनता की अपेक्षाओं का आईना भी होता है। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि यह बजट उद्योग की गति को कितनी रफ्तार देता है और आम नागरिक के जीवन में कितना बदलाव ला पाता है।

'खेलो इंडिया मिशन' के विस्तार और 10 साल के रोडमैप की घोषणा की : पूजा बल्हारा खत्री

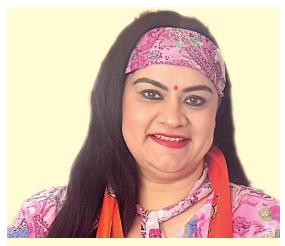

पूजा बल्हारा खत्री
अध्यक्ष, नाथूपुर मंडल सदस्य, ग्रीवंस कमेटी गुरुग्राम।

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| एक पूर्व खिलाड़ी होने के नाते, मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 2026 के केंद्रीय बजट में खेलो इंडिया मिशन के बारे में की गई घोषणा से बहुत खुश हूँ। इस योजना का मकसद टैलेंट को बढ़ावा देना, रोज़गार और मौके पैदा करना है; साथ ही, यह अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स सामान बनाने और इक्विपमेंट डिज़ाइन और मटीरियल साइंस में इनोवेशन के लिए एक खास पहल भी शुरू करेगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में खेलों के लिए 'खेलो इंडिया मिशन' के विस्तार और 10 साल के रोडमैप की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य 2036 ओलंपिक की तैयारी और देश को खेलों का वैश्विक केंद्र बनाना है। बजट में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास, उच्च गुणवत्ता वाले स्पोर्ट्स गुड्स के निर्माण और कोचों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है, साथ ही खेल क्षेत्र के लिए 4480 करोड़ रुपये की संजीवनी दी गई है।

एक स्पोर्ट्स से जुड़ी महिला होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि इस बजट में ज़मीनी सोच दिखती है| यह सभी जमीनी स्तर के खिलाड़ियों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, आइए हम सब मिलकर इसका समर्थन करें! खेलेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया! बजट में महिलाओं के लिए कई विशेष घोषणाएं की गई हैं, जिसमें महिलाओं को लखपति दीदी जैसी योजनाओं से आगे बढ़ाकर बिज़नेस की तरफ लाने की बात सही दिशा है। MSME और छोटे कारोबार को जो सपोर्ट दिया गया है, उससे रोज़गार बढ़ेगा।

गर्ल्स हॉस्टल - कामकाजी महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा व सुविधा के लिए देश के हर जिले में गर्ल हॉस्टल का प्रस्ताव रखा गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को विकसित भारत की नींव रखने वाला ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए हार्दिक बधाई और धन्यवाद देती हूँ। यह बजट अगले 25 वर्षों के सुनहरे भारत की तस्वीर खींचता है।

महिलाओं के नेतृत्व वाली उद्यमशीलता को मिलेगी गति : रुबी सिन्हा

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| ब्रिक्स सीसीआई डब्लूई (वुमेन एंपावरमेंट) की अध्यक्ष और शीएटवर्क की संस्थापक रूबी सिन्हा ने कहा कि आम बजट 2026-27 में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट में 21वीं शताब्दी में तकनीकी वृद्धि पर बल लिया गया है। एसटीईएम में महिलाओं और टेक्नोलॉजी के समावेशी अंगीकार किए जाने पर उनका जोर आगे की सोच और भारत के विकास के लिए समतामूलक दृष्टि को दर्शाता है। लखपती दीदी प्रोग्राम की सफलता के आधार पर क्रेडिट नीत आजीविका से उपक्रम की स्वामी बनने की दिशा में महिलाओं को सहयोग करने का प्रस्ताव दिल खुश करने वाला है। समुदाय के स्वामित्व में स्वयं-सहायता उद्द्यी (एसएचई) मार्ट की स्थापना एक अन्य स्वागत योग्य कदम है जिससे जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को मजबूती मिलेगा। लघु एवं मझोले आकार वाले उपक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

बजट 2026: विकसित भारत की दिशा में दूरदर्शी और समावेशी कदम : विधायक मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा, विधायक, गुरुग्राम।

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| केंद्रीय बजट 2026 को लेकर गुड़गांव के विधायक मुकेश शर्मा ने इसे दूरदर्शी, विकासोन्मुख और समावेशी बजट बताते हुए कहा कि यह आम नागरिक, महिलाएं, युवा, किसान और उद्योग—सभी वर्गों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उनके अनुसार यह बजट केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा नहीं करता, बल्कि भविष्य की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के समाधान का भी स्पष्ट मार्ग प्रस्तुत करता है।

विधायक मुकेश शर्मा ने कहा कि बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और युवा बेटियों के लिए सुरक्षित हॉस्टल, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कौशल विकास के प्रावधान इस बात का संकेत हैं कि सरकार 'नारी शक्ति' को राष्ट्र निर्माण का केंद्र मानती है।

राजधानी चौपाल का विश्लेषण

यह बजट स्पष्ट संकेत देता है कि सरकार की प्राथमिकता दीर्घकालिक विकास, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और औद्योगिक विस्तार पर केंद्रित है। यदि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है, तो हरियाणा सहित पूरे देश में विकास की नई लहर देखी जा सकती है।

यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने की ठोस रणनीति है।

एमएसएमई, रोजगार और उद्योग को मजबूती

बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपये के प्रावधान का उल्लेख करते हुए विधायक ने कहा कि इससे गुरुग्राम जैसे औद्योगिक क्षेत्र में छोटे और मध्यम उद्योगों को नई ताकत मिलेगी, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। औद्योगिक विकास, लॉजिस्टिक्स और रेल कॉरिडोर के विस्तार से व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

पर्यटन, विरासत व पहचान

15 ऐतिहासिक स्थलों के विकास की योजना को उन्होंने हरियाणा के लिए विशेष अवसर बताया। इससे राज्य की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी तथा पर्यटन से जुड़े रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

कृषि और डिजिटल सशक्तिकरण

विधायक ने कहा कि कृषि क्षेत्र में बजट आवंटन बढ़ाना और डिजिटल कृषि मिशन को बढ़ावा देना किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इससे किसानों को तकनीक, बाजार और संसाधनों तक बेहतर पहुंच मिलेगी।

रक्षा, अवसंरचना और कॉरिडोर विकास

रक्षा बजट में वृद्धि, हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार को उन्होंने देश की सुरक्षा और आर्थिक मजबूती से जोड़ा। इससे न केवल रणनीतिक दृष्टि से मजबूती आएगी, बल्कि औद्योगिक और लॉजिस्टिक विकास भी तेज होगा।

मुकेश शर्मा ने कहा कि बजट के तीन मुख्य लक्ष्य—गति, स्थायित्व और समावेशी विकास—भारत को 2047 तक समझदार, सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में निर्णायक कदम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मजबूत आधार तैयार करता है।

आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में सहायक होगा आम बजट : प्रशांत सोलोमन

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल)| केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट को लेकर विभिन्न क्षेत्र के उद्यमियों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हुए बजट को सही मायने में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने वाला बजट बताया है। चिंटेल्स गुरुप के निदेशक और क्रेडाई एनसीआर ईसी/जीसी सदस्य प्रशांत सोलोमन का कहना है कि यह बजट एक आधारभूत ढांचा केंद्रित विजन के साथ दीर्घकालीन मूल्य सृजन करते हुए रीयल एस्टेट एवं ढांचागत क्षेत्रों के लिए एक प्रभावशाली रूपरेखा तैयार करेगा। उनका कहना है कि एक लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड के साथ यह शहरों को आर्थिक गतिविधि के लचीले केंद्र बनाने, समावेशी शहरी विकास एवं टिकाऊ वृद्धि की दिशा में कारगर साबित होगा। टियर-1 और टियर-2 शहरों पर ध्यान दिए जाने से एक विकसित भारत के लिए आधारभूत ढांचे की नीव पडने के साथ निवेश और वृद्धि को गति मिलेगी।

पीलीमंदोरी में गूंजा न्याय का स्वर: पीड़ित परिवार मिला मुख्यमंत्री नायब सैनी से, निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा

सैंकड़ों संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने बैनर-पोस्टर के साथ रखी बात, मुख्यमंत्री ने एसपी सिरसा को फोन कर दिए सख्त निर्देश

आदमपुर मंडी (राजधानी चौपाल)| आदमपुर निवासी समाजसेवी राजकुमार जांगड़ा पर कथित साजिशन हमले और उसके बाद सिरसा पुलिस की एकतरफा कार्रवाई से आक्रोशित आदमपुर क्षेत्र के सैंकड़ों सामाजिक-धार्मिक संगठनों व गणमान्य नागरिकों का प्रतिनिधिमंडल गांव पीलीमंदोरी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिला। बैनर-पोस्टर के साथ पहुंचे लोगों ने न्याय की मांग रखते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई।

प्रतिनिधिमंडल की ओर से राजकुमार जांगड़ा की माता शांति देवी ने ज्ञापन सौंपकर घटनाक्रम से अवगत कराया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आश्वस्त किया कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि "पीड़ित के साथ किसी भी हाल में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, चाहे आरोपित कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो।"

बताया गया कि इससे पहले 23 जनवरी को भी एक प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से मिला था। उस दौरान मुख्यमंत्री ने तुरंत सिरसा के पुलिस अधीक्षक को फोन कर हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पीलीमंदोरी में हुई मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि आश्वासन से न्याय की उम्मीद जगी है, लेकिन कार्रवाई न होने की स्थिति में आंदोलनात्मक रुख अपनाया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में समाजसेवी कृष्ण शाहपुरिया, शांति देवी, रमेश, कुलदीप, प्रेम जांगड़ा, सुरेंद्र, मांगेराम, मदन, जीत कुमार सहित सैंकड़ों लोग शामिल रहे। भारी भीड़ को देखते हुए मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा।

बजट पर प्रतिक्रिया...

हिसार में लिव-इन में रह रही महिला का किडनैप : दीवार फांद कर घुसे युवक, 5 पर केस

हांसी (राजधानी चौपाल) | हांसी जिले के नारनौंद थाना क्षेत्र के गांव गुराना में सोमवार तड़के एक घर में घुसकर मारपीट और एक महिला के अपहरण का मामला सामने आया। आरोप है कि कुछ लोगों ने दीवार कूदकर घर में प्रवेश किया, परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और एक युवक के साथ रिलेशनशिप में रह रही महिला को जबरन गाड़ी में डालकर ले गए। पुलिस ने पीड़ित युवक के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुराना के रहने वाले मोनू ने पुलिस को बताया कि वह वेल्डिंग का काम करता है। उसके अनुसार, शशि नामक महिला 16 जनवरी से उसके साथ रिलेशनशिप में रह रही थी। दोनों 19 जनवरी से हिसार के एक सेफ हाउस में ठहरे हुए थे। इस दौरान नरपेन्द्र ने लोहारू थाने में शशि की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस के सामने शशि ने नरपेन्द्र के साथ जाने से इनकार कर दिया था।

मोनू ने बताया कि 30 जनवरी को वह शशि के साथ अपने घर गुराना आ गया था। 2 फरवरी की सुबह करीब 3:30 बजे नरपेन्द्र, नितेश, प्रदीप (निवासी ढिगावां) और गुराना निवासी सोनू सहित 4-5 अन्य लोग दीवार कूदकर उनके घर में घुस आए। आरोप है कि हमलावरों के हाथों में हॉकी, डंडे और लोहे की रॉड थीं। घर में घुसते ही उन्होंने मोनू और उसके परिजनों के साथ मारपीट शुरू कर दी।

पीड़ित के अनुसार, हमलावर शशि को जबरन घसीटते हुए घर से बाहर ले गए और उसे एक गाड़ी में डालकर अपहरण कर लिया। जाते समय आरोपियों ने मोनू को धमकी दी कि यदि उसने शशि से मिलने की कोशिश की तो उसे जान से मार दिया जाएगा। मोनू ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

खेड़ी चौपटा पुलिस चौकी के प्रभारी सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को सरकारी अस्पताल हांसी से हिसार रेफर किया गया था। डॉक्टरों द्वारा बयान के लिए फिट घोषित किए जाने के बाद मोनू का बयान दर्ज किया गया। पुलिस ने मोनू के बयान के आधार पर नरपेन्द्र, नितेश, प्रदीप, सोनू और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।

भिवानी में रेप के दोषी को 20 वर्ष कारावास : 30 हजार का जुर्माना, साथी को 7 साल कैद

भिवानी (राजधानी चौपाल)| भिवानी में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और रेप करने के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 20 वर्ष कारावास व 30 हजार जुर्माना और उसके साथी को 7 वर्ष कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। यह सजा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुरुचि अटरेजा सिंह की कोर्ट द्वारा सुनाई गई है। पीड़िता के पिता के द्वारा थाना सदर पुलिस भिवानी में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपियों के द्वारा उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले गए और रेप किया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। ट्रायल के दौरान पुलिस द्वारा प्रभावी जांच, साक्ष्य एवं दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।

कोर्ट ने मुख्य आरोपी हिसार के गांव कर्बला निवासी अमित कुमार को पॉस्को एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया। धारा 363 आईपीसी के तहत 7 वर्ष कारावास व 5000 जुर्माना। धारा 366 आईपीसी के तहत 10 वर्ष कारावास व 5000 जुर्माना लगाया है।

वहीं, दूसरे आरोपी हिसार के गांव खरबला निवासी साहिल को धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 वर्ष कैद व 5000 रुपए का जुर्माना, धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 वर्ष कैद व 5000 का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि महिलाओं एवं नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों में त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ित को समय पर न्याय दिलाना जिला पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

एचएयू में दो सहायक प्रोफेसरों पर छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के लगाए आरोप, निलंबित

हिसार (राजधानी चौपाल) | हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में एक पीएचडी छात्रा ने कॉलेज के दो शिक्षकों पर छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। छात्रा ने कॉलेज डीन को इसकी शिकायत लिखित भी दी है। शिकायत मिलते ही विवि प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉ. नवीन कौशिक और डॉ. अजीब को निलंबित कर दिया है और जांच के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी है। यह जांच कमेटी अब छात्रा की शिकायत पर जांच आरंभ करेगी। जांच को किसी तरह से प्रभावित न किया जा सके इसलिए विवि प्रशासन ने दोनों शिक्षकों को निलंबित किया है।

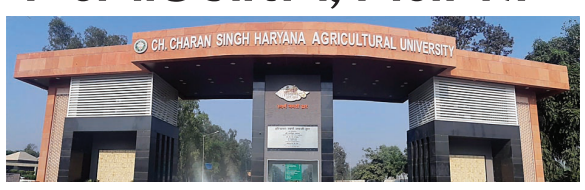

जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी।

जांच कमेटी शिकायत के हर पहलू पर जांच करेगी। जिसमें डिजिटल साक्ष्य के रूप में सीसीटीवी कैमरे और हाजिरी रजिस्टर चैक किए जाएंगे। यह देखा जाएगा कि रिसर्च प्रोजेक्ट को लेकर किसी तरह का दबाव था या नहीं। इससे पहले भी क्या आरोपी शिक्षकों के खिलाफ किसी तरह की शिकायत रही है या नहीं। इसके अलावा सहकर्मियों और दूसरे शोधार्थियों से भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच किसी तरह की कॉल या व्हाट्सएप चैक को लेकर भी जांच होगी। वहीं इस मामले में एचएयू प्रशासन का कहना है कि शिकायत प्राप्त होते ही निष्पक्ष जांच के लिए दोनों वैज्ञानिकों को निलंबित किया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए जांच समिति गठित कर दी गई है। जांच रिपोर्ट के बाद ही नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

हिसार में छात्राओं ने आकाशवाणी केंद्र का भ्रमण किया : सामाजिक विषयों पर गीत गाए

हिसार (राजधानी चौपाल)| हिसार के आकाशवाणी केंद्र में बुधवार को राजकीय कन्या उच्च विद्यालय सीसवाला की छात्राओं ने बालसभा कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान छात्राओं ने भारतीय संस्कृति, नशा मुक्ति और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे सामाजिक विषयों पर आधारित संस्कृत गीत, गीतिकाएं, कविताएं और सामूहिक गीत प्रस्तुत किए। टीचर सरोज बाला और सुरेश कुमार ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत संस्कृत गीतिका से हुई। इसके बाद छात्राओं ने नशा मुक्ति पर प्रभावशाली कविताएं व गीत प्रस्तुत किए। साथ ही, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को प्रेरित करने वाली रचनाएं भी पेश की गईं। सभी प्रस्तुतियों में छात्राओं का आत्मविश्वास और कला कौशल स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। छठी कक्षा की अक्षु, भावना, रिया, डिंपल, धापली, निधि, अमीषा, सातवीं कक्षा की साक्षी, प्रिया, रिया, प्राची तथा आठवीं कक्षा की साक्षी, सोनाक्षी, शिक्षा और अंजलि ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को यादगार बना दिया। कार्यक्रम में उपस्थित श्रोताओं और आयोजकों ने छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने सभी छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की।

सीएम कप के लिए फुटबॉल, हैंडबॉल और बास्केटबॉल टीमों का चयन

हिसार (राजधानी चौपाल) | सीएम कप खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के चयन के लिए जिले में ट्रायल किये गए। जाट कॉलेज में फुटबॉल का ट्रायल लिया गया। महाबीर स्टेडियम में हैंडबॉल और बास्केटबॉल के ट्रायल हुए। जिलेभर से 200 खिलाड़ी पहुंचे। फुटबॉल की 18 बॉयज और 18 गर्ल्स खिलाड़ियों को चुना गया। जिला हैंडबॉल कोच अनूप कसवां ने बताया कि ट्रायल जिला खेल अधिकारी नरेश कुमार की देखरेख में हुए। हैंडबॉल में कुल 54 पुरुष और 57 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। जिनमें से चयन किया गया। बास्केटबॉल में भी करीब 60 से अधिक खिलाड़ी उपस्थित रहे। चयनित खिलाड़ियों को गुरुग्राम और पलवल में होने वाली सीएम कप प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को कबड्डी, वॉलीबॉल खो-खो का ट्रायल लिए जाएंगे।

इस अवसर पर पूर्व साई हैंडबॉल कोच राकेश सोलंकी, कोच राजेंद्र बूरा, सतबीर पानू, पूजा कसवां, महावीर पूनिया, संदीप पूनिया, कपिल कुमार, पवन शर्मा, राजेश ग्रेवाल, कृष्ण शर्मा, सुमन जाखड़, प्रदीप जांगड़ा सहित खेल विभाग के अन्य कोच मौजूद रहे।

चयनित खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री कप प्रतियोगिता का आयोजन 9 से 11 फरवरी तक गुरुग्राम और पलवल में किया जाएगा। हरियाणा सीएम कप में प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख, द्वितीय पुरस्कार 51 हजार और तृतीय पुरस्कार 31 हजार दिए जाएंगे।

जिले की पहली मॉडल रोड बनेगी मिर्जापुर-नियाणा सड़क; 10 मीटर चौड़ाई होगी

प्रदेश सरकार की हर जिले में एक मॉडल रोड योजना के तहत चयन

हिसार (राजधानी चौपाल) | प्रदेश सरकार की हर जिले में एक मॉडल रोड योजना के तहत हिसार में मिर्जापुर-नियाणा रोड को चौड़ा किया जाएगा। सीएम अनाउंसमेंट के तहत चयनित इस रोड को मॉडल रोड के रूप में डेवलप करने के लिए मुख्यालय ने बीएंडआर विभाग को सहमति दे दी है। करीब 15 किलोमीटर लंबी यह सड़क अब न केवल चौड़ी होगी, बल्कि हाईटेक सुविधाओं से भी लैस होगी। वर्तमान में इसकी चौड़ाई 7 मीटर है, जिसे बढ़ाकर 10 मीटर किया जाएगा। इस रोड से आसपास के कई गांवों के लिंक रोड होने से करीब 10 गांवों की हजारों की आबादी को सुगम रास्ता मिल पाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में फिर यह रोड हांसी जिले तक चौड़ा हो जाएगा। इसकी चौड़ाई साउथ बाइपास इतनी की जाएगी।

यह रोड नेशनल हाईवे नंबर-9 (मिर्जापुर चौक) से शुरू होकर नियाणा गांव तक जाएगी। वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए विभाग ने इसके चौड़ीकरण का प्रस्ताव तैयार किया है। करीब 15 किलोमीटर रोड

का कायाकल्प किया जाएगा।

इन 10 गांवों को मिलेगा सीधा फायदा : धान्सू - राजली -घिराय - सुलखनी - खानपुर सिंधड़ - सिंघवा - चानौत - खरड़ अलीपुर - मिर्जापुर - नियाणा

मॉडल रोड में यह खास होगा : 1. रोड फर्नीचर : सुरक्षा के लिहाज से रिफ्लेक्टर, साइन बोर्ड और मार्किंग जैसे आधुनिक रोड फर्नीचर लगेंगे। 2. स्पेशल बर्म : सड़क के किनारे मॉडल बर्म बनाए जाएंगे, जिस पर टू-व्हीलर आसानी से चल सकेंगे। इससे मुख्य सड़क पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और हादसे घटेंगे।

पीडब्ल्यूडी के एसई अजीत सिंह ने बताया कि सीएम ने मॉडल रोड की घोषणा की थी, जिसमें हिसार की मिर्जापुर-नियाणा रोड का चयन हुआ है। पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा ने एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अगले सप्ताह तक एस्टीमेट मुख्यालय भेज दिया जाएगा।

बीडीपीओ ऑफिस में फाइलों का अंबार देख डीसी बोले- काम में देरी बर्दाश्त नहीं

हिसार (राजधानी चौपाल) | जिला उपायुक्त महेंद्र पाल ने गुरुवार को स्थानीय खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त के तेवर सख्त नजर आए। उन्होंने न केवल फाइलों के रख-रखाव को देखा, बल्कि पेंडिंग पड़े कामों पर अधिकारियों की क्लास भी लगाई।

उपायुक्त ने दो टूक कहा कि सरकारी दफ्तरों में फाइलें घुमाने का दौर बंद करें और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाएं। प्रशासन की प्राथमिकता सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना है। जिला प्रशासन ग्रामीण विकास और पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग करता रहेगा।

इस दौरान उपायुक्त ने कार्यालय परिसर की साफ-सफाई पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि एक स्वच्छ वातावरण ही कार्यकुशलता को बढ़ाता है। कर्मचारियों को हिदायत देते हुए उन्होंने कहा, 'दफ्तर आने वाले आम नागरिकों के साथ व्यवहार शालीन और संवेदनशील रखें। आपकी मेज पर आई फाइल किसी की उम्मीद हो सकती है, उसे बिना कारण न अटकाएं।

42वीं मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में विजेता सोहन सिंह ने जीता कांस्य पदक

हिसार (राजधानी चौपाल) | केरल के त्रिवेंद्रम में आयोजित 42वीं मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) में कार्यरत धावक सोहन सिंह ने 35 अधिक आयु वर्ग की 800 मीटर दौड़ में 2 मिनट 11 सैकेंड का समय लेकर कांस्य पदक जीता। हिसार पहुंचने पर निगम ने उनका सम्मान किया। यह समारोह डीएचबीवीएन के सेक्टर 1 और 4 कार्यालय तथा सिटी कार्यालय में संपन्न हुआ। समारोह में निगम के उप मंडल अधिकारी मनदीप कुंडू और कार्यालय के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने सोहन सिंह को फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया।

हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने 12 फरवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी

हिसार (राजधानी चौपाल) | हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन एवं संबंधित सर्व कर्मचारी संघ ने 12 फरवरी 2026 को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारी तेज कर दी है। हिसार डिपो में रोडवेज कर्मचारियों ने नेताओं का स्वागत किया और गेट मीटिंग में राज्य महासचिव सुमेर सिवाच, वरिष्ठ उपप्रधान शिव कुमार और हिसार डिपो प्रधान राजकुमार चौहान ने कर्मचारियों को संबोधित किया। जत्थे के अनुसार, हिसार डिपो के सभी लिपिक, चालक, परिचालक, मैकेनिक और निरीक्षक हड़ताल में शामिल होंगे। सुमेर सिवाच ने बताया कि पिछली बातचीत में कई आश्वासन दिए गए थे, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया। हड़ताल के माध्यम से कर्मचारी सरकार से शीघ्र समाधान और सभी लंबित मांगों के पूरा होने की अपील करेंगे।

अग्रोहा के पावरलिफ्टर ने जीता गोल्ड मेडल : नोएडा में हुई नेशनल चैंपियनशिप, गांव में जश्न मनाया

उकलाना (राजधानी चौपाल) | हिसार के गांव मोहब्बतपुर निवासी युवा पावर लिफ्टर वरुण सागर ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है। नोएडा में आयोजित डब्ल्यूपीसी इंडिया इक्विप्ड नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में वरुण सागर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

इस प्रतियोगिता में देशभर से आए नामी पावरलिफ्टर्स ने हिस्सा लिया। कड़े मुकाबले के बीच वरुण सागर ने अपनी ताकत और तकनीक का लोहा मनवाते हुए गोल्ड मेडल जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। मंगलवार को जैसे ही वरुण की इस ऐतिहासिक जीत की सूचना अग्रोहा पहुंची, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई।

वरुण सागर के अग्रोहा आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। डीजे पर देशभक्ति गीतों की गूंज, फूलमालाओं व गुलदस्तों के साथ

सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में वरुण सागर को लांधड़ी टोल से विनायक सिटी, अग्रोहा तक सम्मानपूर्वक लाया गया।

विनायक सिटी पहुंचने पर विजेता वरुण सागर ने अपने दादा प्रह्लाद राय शर्मा सहित परिवार के सभी वरिष्ठजनों का आशीर्वाद लिया। वरुण सागर के पिता विद्या सागर शर्मा ने बताया कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए वरुण ने लंबे समय तक कठोर अभ्यास और अनुशासन का पालन किया। यह स्वर्ण पदक उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और कोच के कुशल मार्गदर्शन का परिणाम है। हमें गर्व है कि वरुण ने परिवार, गांव, जिला और राज्य का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है।

इस अवसर पर विनायक सिटी परिवार के सदस्यों मनदीप किरमारा, अजित कालीरावण, मुकेश सिंगला, प्रदीप सिहाग, मास्टर लाल सिंह, राजा सरपंच, रामफल, राजपाल, भरता जाखड़, ईश्वर शर्मा, प्रदीप शर्मा, सुरेश शर्मा फौजी, अश्विन जाखड़, सोनू बंसल, मांगेराम बंसल, सतीश शर्मा लांधड़ी, दयानंद शर्मा, मोनू, हैप्पी मूंड, सुरेश लांधड़ी, कालू भादू सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने वरुण सागर को बधाई देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

एचएयू स्टूडेंट आरती, परीनिल, परमिंदर और राजबाला करेंगे जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में रिसर्च

जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के साथ है एचएयू का एमओयू

हिसार (राजधानी चौपाल) | हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के चार विद्यार्थी टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जापान में शोध करेंगे। एचएयू का टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जापान के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू है। कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज भी हाल ही में जापान का दौरा करके आए हैं। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, शोध और इंटर्नशिप के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे। एचएयू के कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कृषि कॉलेज और बेसिक साइंस कॉलेज के विद्यार्थियों का चयन हुआ है। इन विद्यार्थियों का खर्च भी यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो उठाएगा।

एचएयू के वीसी प्रो. बीआर काम्बोज ने बताया कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी न केवल विदेशों में पढ़ाई के लिए जाते हैं बल्कि विदेशों से भी अनेक छात्र यहां पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जापान के दो विश्वविद्यालयों के साथ विवि का एमओयू किया हुआ है। इसके तहत विद्यार्थी उच्च शिक्षा और शोध के लिए जापान जा रहे हैं। विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक्सपोजर मिल रहा है।

कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की छात्रा आरती खिप्पल का चयन टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, जापान में पीएचडी के लिए हुआ है। छात्रा का सारा खर्च टोक्यो यूनिवर्सिटी द्वारा वहन किया जाएगा। आरती इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक्स विषय पर शोध करेंगी। उनके शोध कार्य का मार्गदर्शन प्रो. इरीए केनजी तथा डॉ. बाबिल द्वारा किया जाएगा। स्नातकोत्तर में आरती ने गेहूं में रतुआ रोग के विरुद्ध प्रतिरोध प्रदान करने वाले जीन की पहचान पर शोध किया। उनका यह शोध भविष्य में रोग प्रतिरोधी गेहूं की किस्म के विकास और क्रॉप इम्प्रूवमेंट में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आरती जींद की रहने वाली है।

एमएससी छात्र परमिंदर इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल डेवलमेंट विभाग के ट्रॉपिकल क्रॉप साइंस लैब में डॉ. हिरोनोबू शिवाची व एसोसिएट प्रो. पचक्किल बाबुल के मार्गदर्शन में अध्ययन करेंगे। परमिंदर अलग-अलग सूखे के तनाव के तहत मूंगफली के फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म को समझना शीर्षक पर अपना शोध करेंगे।

मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग की छात्रा राजबाला यादव का टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, जापान में पीएचडी के लिए चयन हुआ है। इस दौरान पढ़ाई, छात्रवृत्ति व रहने का शुल्क टोक्यो यूनिवर्सिटी जापान द्वारा वहन किया जाएगा। रेवाड़ी राजबाला टोक्यो यूनिवर्सिटी के परिसर माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला में डॉ. उचीनों के साथ फरमेंटिड फूड में जीवाणुओं की विविधता और गुणवत्ता पर काम करेंगी। परिनील एमएससी की छात्रा है। जो एक्सचेंज वैगनिंगन यूनिर्सिटी एंड रिसर्च के इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल डेवलमेंट विभाग की ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर साइंस लैब में प्रो. काइहेई कोशियों के मार्गदर्शन में अपना अध्ययन करेंगी। परिनील करेले के बीजों की स्ट्रेस टॉलरेंस पर पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल 6000 का प्रभाव पर शोध करेगी।

राहुल गांधी और रवनीत बिट्टू के बीच की तकरार ने पकड़ा तूल; 'बंधुआ मजदूर' और 'फिजिकल अटैक' के आरोपों से सिसायी गलियारे में हड़कंप

नई दिल्ली/चंडीगढ़/लुधियाना (राजधानी चौपाल)| भारतीय लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद परिसर में इन दिनों जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसने न केवल राजनीतिक मर्यादाओं को तार-तार किया है, बल्कि देश की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी है जिसे भरना निकट भविष्य में संभव नहीं दिखता। हालिया घटनाक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच हुई तीखी नोकझोंक ने अब एक बड़े व्यक्तिगत और वैचारिक युद्ध का रूप ले लिया है। बिट्टू ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें 'हमलावर' और कांग्रेस सांसदों को 'गांधी परिवार का बंधुआ मजदूर' करार दिया है।

संसद परिसर में क्या हुआ?

कल संसद भवन के बाहर उस समय सनसनी फैल गई जब केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू और राहुल गांधी आमने-सामने आ गए। बिट्टू के अनुसार, जैसे ही उन्होंने राहुल गांधी से हाथ मिलाने से इनकार किया, राहुल गांधी आपा खो बैठे। बिट्टू ने दावा किया है कि राहुल गांधी उनकी ओर शारीरिक हमला (Physical Attack) करने के इरादे से बढ़े थे।

बिट्टू ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'जब मैंने हाथ नहीं मिलाया तो राहुल गांधी इतने गुस्से में आ गए कि वे मुझे पीटने के लिए आगे बढ़े। अगर वहां मौजूद कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा बीच-बचाव नहीं करते, तो स्थिति बेहद खराब हो सकती थी। वे शायद मेरी पगड़ी उतारने की कोशिश करते।'

'बंधुआ मजदूर' और 'गांधी परिवार' का वार

रवनीत बिट्टू, जो कभी राहुल गांधी के सबसे करीबी सिपहसालारों में गिने जाते थे, आज उनके सबसे कट्टर आलोचक बनकर उभरे हैं। उन्होंने कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस अब वह पुरानी कांग्रेस नहीं रही जो विचारधारा पर चलती थी।

बिट्टू ने कहा, 'कांग्रेस अब सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है। वहां सांसद अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, बल्कि वे गांधी परिवार के 'बंधुआ मजदूर' की तरह काम कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। अगर कांग्रेस में कोई नैतिकता बची होती, तो अनुशासनहीनता के लिए सबसे पहले राहुल और प्रियंका को ही सस्पेंड किया जाना चाहिए था।' उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी सांसदों को उकसाकर टेबलों पर चढ़वा देते हैं, उन्हें सस्पेंड करवा देते हैं, और खुद अपनी आलीशान गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। पीछे रह जाते हैं वे सांसद जिनका करियर दांव पर लगा होता है।

बिट्टू की अपनी साख और कांग्रेस का इतिहास

राहुल गांधी के उन समर्थकों को जवाब देते हुए जो कह रहे हैं कि बिट्टू को पहचान कांग्रेस ने दी, बिट्टू ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'मैं कांग्रेस पर कभी बोझ नहीं बना। अगर मैं सांसद बना तो अपनी मेहनत और जनता के वोट से बना। अगर मैं यूथ कांग्रेस का प्रधान बना तो चुनाव जीतकर बना। मुझे किसी ने खैरात में पद नहीं दिए।' बिट्टू का यह बयान उन कांग्रेस नेताओं के लिए था जो उन्हें 'गद्दार' कहकर संबोधित कर रहे हैं। भाजपा ने इस मुद्दे को हाथों-हाथ लिया है और इसे एक 'स्वाभिमानी सिख' बनाम 'अहंकारी नेता' की लड़ाई करार दिया है।

सिखों के अपमान और पुरानी यादों का जिन्न

इस पूरे विवाद ने पंजाब की राजनीति में एक पुराना और गहरा जख्म कुरेद दिया है। राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए बयानों के बाद जब बिट्टू ने स्टैंड लिया, तो कांग्रेस ने उन्हें निशाना बनाया।

भाजपा का पक्षः भाजपा का स्पष्ट मानना है कि बिट्टू को 'गद्दार' कहना केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि पूरी सिख कौम का अपमान है। भाजपा ने इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के दंगों की मानसिकता से जोड़ा है।

कांग्रेस की सफाईः पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने बिट्टू पर पलटवार करते हुए उनका एक पुराना वीडियो साझा किया, जिसमें बिट्टू राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। वड़िंग ने कहा कि बिट्टू ने ही राहुल गांधी को उकसाया और उन पर घटिया टिप्पणी की।

क्या पंजाब में कांग्रेस ने कर दिया 'सेल्फ गोल'?

'राजधानी चौपाल' के विश्लेषण के अनुसार, यह विवाद कांग्रेस के लिए पंजाब में भारी पड़ सकता है। पंजाब पहले से ही गुटबाजी और दलित-सिख समीकरणों में उलझा हुआ है। बिट्टू जैसे कद्दावर नेता, जिनका परिवार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में शहीद हुआ है, उन्हें इस तरह निशाने पर लेना सिखों के एक बड़े वर्ग को नाराज कर सकता है। ग्राउंड लेवल पर लोग अब यह पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी की राजनीति पंजाब में कांग्रेस को और कमजोर कर देगी?

लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी

संसद में नेताओं का एक-दूसरे पर शारीरिक हमले के लिए बढ़ना या व्यक्तिगत छींटाकशी करना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। 'राजधानी चौपाल' अपनी जनता के मंच से यह सवाल पूछता है कि क्या राजनीति अब मुद्दों से हटकर केवल व्यक्तिगत दुश्मनी तक सीमित रह गई है? रवनीत बिट्टू के आरोपों में कितनी सच्चाई है, यह तो सीसीटीवी फुटेज या जांच का विषय है, लेकिन इस घटना ने राहुल गांधी की 'मोहब्बत की दुकान' के स्लोगन पर बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं।

किसके इशारे पर खड़े हो रहे हैं अवैध वेयरहाउस?

गुरुग्राम के रेजेंट पार्क, संत प्रकाशपुरी मंदिर के पास खुलेआम नियमों की धज्जियाँ -प्रशासन की चुप्पी पर बड़े सवाल

गुरुग्राम (राजधानी चौपाल) | गुरुग्राम में अवैध निर्माण कोई नई बात नहीं, लेकिन रेजेंट पार्क इलाके में संत प्रकाशपुरी मंदिर के नजदीक जिस बेखौफ अंदाज़ में अवैध वेयरहाउस खड़े किए जा रहे हैं, उसने प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि सिस्टम की खामोशी का जीता-जागता उदाहरण बन चुका है।

रिहायशी क्षेत्र में बिना किसी रोक-टोक के टीनशेड और बड़े ढांचे खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। हैरानी की बात यह है कि जहां यह निर्माण हो रहा है, वहां से प्रशासनिक तंत्र की नजर बचना संभव नहीं लगता — फिर भी कार्रवाई शून्य है।

सवाल यह है कि इन वेयरहाउस में आज क्या रखा जा रहा है, उससे बड़ा सवाल यह है कि भविष्य में यहां क्या गतिविधियाँ होंगी? केमिकल स्टोरेज? ज्वलनशील सामान? कोई अवैध गतिविधि? कुछ महीने पहले ही गुरुग्राम में वेयरहाउस में लगी भीषण आग ने पूरे सिस्टम की आंखें खोल दी थीं। क्या उस घटना से भी कोई सबक नहीं लिया गया? नगर निगम के अधिकारी इस मामले में मौन साधे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक कोई बड़ा हादसा न हो जाए, तब तक फाइलें नहीं खुलतीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।

कड़ा सवाल...

Q. क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के गुरुग्राम जैसे शहर में इतना बड़ा अवैध निर्माण संभव है?

Q. क्या छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके असली जिम्मेदारों को बचाया जाएगा?

सख्त कार्रवाई हो...

अब समय आ गया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो इस पूरे प्रकरण की जांच करे। अवैध निर्माण को संरक्षण देने वाले अधिकारियों और संबंधित लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो। गुरुग्राम को हादसों के इंतजार में नहीं छोड़ा जा सकता।

न्यूज ब्रीफ

रोजगार की तलाश में विदेश गए युवाओं की दुर्दशा के लिए भाजपा जिम्मेदार: दीपेंद्र

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा में नियम-377 के तहत रूस-यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीय युवाओं, विशेषकर छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि यह मामला भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सरकार की विदेश नीति से सीधे जुड़ा हुआ है। कई युवा रोजगार या पढ़ाई के लिए रूस गए थे, लेकिन एजेंटों द्वारा धोखे से उन्हें रूसी सेना में भर्ती कर युद्ध क्षेत्र में झोंक दिया गया। हुड्डा ने मांग की कि सरकार इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दे और कूटनीतिक माध्यमों से रूसी सरकार से बातचीत कर सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि वे पहले भी विदेश मामलों की संसदीय समिति व विदेश राज्य मंत्री के समक्ष यह मामला उठा चुके हैं। उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि रोजगार की कमी ने युवाओं को विदेश जाने पर मजबूर किया है

रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहना सिख समाज का अपमान, राहुल गांधी माफी मांगें : बड़ौली

सोनीपत (राजधानी चौपाल)| राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहे जाने के विरोध में भाजपा ने दूसरे दिन भी प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की अगुवाई में सुभाष चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन कर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। बड़ौली ने कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहना केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे सिख समाज का अपमान है। उन्होंने राहुल गांधी से सिख समाज से सार्वजनिक माफी की मांग की। उन्होंने दावा किया कि सोनीपत, अम्बाला और पंचकूला निकाय चुनावों में भाजपा का कमल खिलेगा। उधर, भाजपा पं. दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप में मनाएगी।

स्टार्टअप में महिलाओं की भागीदारी को 60 प्रतिशत करने का लक्ष्यः मुख्यमंत्री

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल)| स्टार्टअप व उद्यमिता के लिए 7,500 करोड़ रुपए के प्रावधान से प्रदेश नमन, का स्टार्टअप इकोसिस्टम और मजबूत होगा। इससे प्रदेश में नवाचार बढ़ेगा व युवा रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि देने वाले बनेंगे। हरियाणा देश में स्टार्टअप में चौथे बड़े राज्य के रूप में उभरा है। प्रदेश सरकार ने अगले चरण में स्टार्टअप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। यह जानकारी सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। सीएम ने कहा कि सरकार नीति आयोग से मिलकर 'महिला उद्यमिता मंच' का 'स्टेट चैप्टर' स्थापित कर रही है। इससे महिला उद्यमियों को 700 से अधिक मेंटर्स, विशेष प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बाजार तक पहुंच और इन्क्यूबेशन सहयोग मिलेगा। सरकार स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए 2 हजार करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स स्थापित करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोटेक व साइबर सिक्योरिटी तकनीकों के लिए 10 हजार करोड़ का विशेष फंड रखा है। इसका लाभ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला व रोहतक जैसे शैक्षणिक व तकनीकी केंद्रों को मिलेगा, जहां युवा कौशल सीखकर उच्च-आय रोजगार पा सकेंगे। खेलों के क्षेत्र में 'खेलो इंडिया मिशन' को एकीकृत प्रतिभा विकास मार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें वैज्ञानिक प्रशिक्षण, आधुनिक खेल अवसंरचना व तकनीक का समावेश होगा। प्रदेश की लगभग 65% आबादी युवा है व यह बजट इस युवा शक्ति को शिक्षा, कौशल, तकनीक व रोजगार से जोड़ने का स्पष्ट रोडमैप देता है।

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा- रोडवेज बसों का ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जा रहा

उकलाना (राजधानी चौपाल) | प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से सभी पुराने बिजली मीटर बदले जाएंगे और उनकी जगह आधुनिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जिस तरह से मोबाइल सेवाओं में प्रीपेड और पोस्टपेड विकल्प उपलब्ध होते हैं, उसी तर्ज पर स्मार्ट मीटर में भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी। यह बात बिजली मंत्री अनिल विज ने भाजपा नेता डॉ. योगेश बिदानी के आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही।

विज ने बताया कि भूमिगत बिजली तारें बिछाने की प्रक्रिया गुरुग्राम और फरीदाबाद में शुरू कर दी गई है। परिस्थितियों के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी अंडरग्राउंड केबल डाली जाएंगी, जिससे खंभे गिरने या ऊपर से तार टूटने जैसी समस्याओं से निजात मिले। उन्होंने बताया कि खेदड़ थर्मल पावर प्लांट में नई यूनिट स्थापित की जाएगी, इसके लिए कोल लिंकेज की मंजूरी भी मिल चुकी है। बिजली मंत्री अनिल विज ने बताया कि सभी अधीक्षण अभियंताओं एसई को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिदिन सुबह 11 बजे तक यह जानकारी दें कि उनके क्षेत्र में यदि कहीं बिजली कट लगा है तो उसका कारण, अवधि और परिस्थितियां क्या रही हैं। लगभग पूरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति संतोषजनक रही है और केवल 6 अधीक्षण अभियंताओं से ही स्पष्टीकरण मांगा गया है। बिजली की मांग के अनुरूप सभी ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने अपग्रेडेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है।

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए बसों में ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे बसों की आवाजाही की जानकारी मिल सकेगी। इस दिशा में सभी बस अड्डों पर डिजिटल डिस्प्ले पैनल लगाए जाएंगे तथा एक मोबाइल एप भी विकसित की जा रही है। यात्री बस की लोकेशन, रूट और समय की जानकारी मोबाइल पर पा सकेंगे। ई- बसों की संख्या बढ़ाने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष डॉ. आशा खेदड़, मीडिया प्रभारी राजेन्द्र सपड़ा, रामचन्द्र गुप्ता और डॉ. योगेश बिदानी थे।

मंत्री ने बिजली अधिकारी को लगाई फटकार

उकलाना हरियाणा के बिजली, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज मंगलवार को हरियाणा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के पूर्व चेयरमैन श्रीनिवास गोयल के आवास पर पहुंचे। जहां कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आमजन की समस्याएं सुनीं। बड़ी संख्या में लोगों ने बिजली विभाग से जुड़ी समस्याएं उनके समक्ष रखीं और बिजली अधिकारियों के रवैये को लेकर शिकायतें कीं। लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली निगम के अधिकारी जनता की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मौके पर ही उकलाना बिजली निगम के एसडीओ को तलब किया और कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि 'मैं भी और आप भी जनता के नौकर हैं। जनता की समस्याओं का समाधान करना हमारा कर्तव्य है।

संसदीय इतिहास में 21 साल बाद फिर वही मंजरः बिना पीमए के भाषण के पास हुआ धन्यवाद प्रस्ताव

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल) | भारतीय संसद के बजट सत्र के दौरान एक ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है, जिसने दो दशक पुराने इतिहास की यादें ताजा कर दीं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के ही पारित कर दिया गया। संसदीय परंपराओं के अनुसार, इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री का जवाब होना अनिवार्य माना जाता है, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे और आसन के प्रति कड़े रुख के चलते यह संभव नहीं हो सका।

विपक्ष का कड़ा रुख और राहुल गांधी का मुद्दा हंगामे की मुख्य जड़ कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने की अनुमति न मिलना बताया जा रहा है। कांग्रेस सांसदों का आरोप है कि राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख की एक अप्रकाशित किताब और कुछ विशेष व्यापारिक सौदों (ट्रेड डील) पर अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक राहुल गांधी को अपनी बात रखने की इजाजत नहीं मिलती, विपक्ष प्रधानमंत्री को सदन में बोलने नहीं देगा।

स्पीकर की पीड़ा और सुरक्षा की चिंता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में हुए इस घटनाक्रम पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि बुधवार शाम को जब प्रधानमंत्री को जवाब देना था, तब विपक्षी महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर लिया था और वहां पोस्टर लहराए जा रहे थे।

स्पीकर ने कहा कि ऐसी स्थिति में किसी भी अप्रत्याशित घटना को टालने के लिए उन्होंने खुद प्रधानमंत्री से सदन में न आने का आग्रह किया था। उन्होंने इसे लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ बताया।

साल 2004 का वह काला दिन

संसद के रिकॉर्ड के अनुसार, यह स्थिति 21 साल बाद दोबारा बनी है। इससे पहले 10 जून 2004 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तब तत्कालीन विपक्ष ने भारी हंगामे के चलते उन्हें धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने नहीं दिया था। आज ठीक वैसी ही तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के मामले में दिखाई दी, जहाँ सदन के नेता का भाषण हंगामे की भेंट चढ़ गया।

पीएम की 97 मिनट की 'दहाड़'

भले ही लोकसभा में प्रधानमंत्री का भाषण नहीं हो सका, लेकिन राज्यसभा में उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर करीब 97 मिनट तक विस्तृत जवाब दिया। हालांकि, वहां भी शुरुआत में विपक्षी सांसदों ने भारी नारेबाजी की और बाद में पूरी कांग्रेस व विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सत्ता पक्ष ने इसे 'संसदीय शिष्टाचार की हार' बताया है, वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि सरकार आखिर किस बात से डर रही है।

कृषि को लाभकारी बनाए बिना ग्रामीण समृद्धि संभव नहीं : नायब

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बदलते समय में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का समाधान परंपरागत तरीकों से नहीं, बल्कि नवाचार, तकनीक और संस्थागत वित्तीय सहयोग से ही संभव है। वे गुरुवार को नाबार्ड द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय ऋण संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सीएम ने नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया वर्ष 2026-27 का स्टेट फोकस पेपर भी रिलीज किया, जिसमें हरियाणा की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण क्षमता 3 लाख 67 हजार करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 17 फीसदी की वृद्धि को दर्शाती है। इस मौके पर सीएम ने अनेक समितियों को बेहतर कार्यों के लिए सम्मानित भी किया।सीएम सैनी ने कहा, 'कृषि को लाभकारी बनाए बिना ग्रामीण समृद्धि संभव नहीं है। इसके लिए 'कम भूमि में अधिक उत्पादन' और 'पर ड्रॉप-मोर क्रॉप' को अपनाना होगा। आगामी बजट में स्मार्ट एग्रीकल्चर जोन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार अनेक कदम उठा रही है। इस दौरान नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक निवेदिता तिवारी ने बताया कि कृषि के लिए 1.32 लाख करोड़ व एमएसएमई क्षेत्र के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपए की ऋण संभावनाएं हैं।

कनाडाई प्रतिनिधिमंडल ने की सीएम से मुलाकात : सीएम सैनी से बुधवार देर शाम चंडीगढ़ में कनाडा के अल्बर्टा प्रांत की स्वदेशी संबंध मंत्री राजन साहनी के नेतृत्व में आए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। 'संत कबीर कुटीर' पर इस दौरान दोनों पक्षों के बीच निवेश, नवाचार, शिक्षा, कौशल विकास व आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। सीएम ने कहा, 'हरियाणा वैश्विक सहयोगों के लिए हमेशा तैयार है, जिससे प्रदेश में कौशल वृद्धि, नवाचार व आर्थिक विकास को गति मिले।

भाजपा मतपत्र से चुनाव करवा ले तो उनको लोकप्रियता का पता चल जाएगा : राव नरेंद्र सिंह

बोले - कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में एसवाईएल पर निर्णय दे रखा है, भाजपा सरकार इसे बनवाए

हिसार (राजधानी चौपाल) | भाजपा मतपत्र से चुनाव करवाकर देख ले, उनको लोकप्रियता का पता चल जाएगा। कांग्रेस के समय भी ईवीएम थी, लेकिन कभी किसी को शक नहीं था। कांग्रेस अगर गड़बड़ी करती तो भाजपा कभी सत्ता में नहीं आ पाती। यह बात कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बुधवार को हिसार में प्रेसवार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हरियाणा के विस चुनाव में भी गड़बड़ी हुई है।

राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को खत्म किया जा रहा है। गरीबों के 100 दिन के काम की कानूनी गारंटी को व्यवहार में कमजोर किया जा रहा है। महात्मा गांधी के नाम पर बने इस कानून को केंद्र सरकार ने बदल दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा दोनों जगह भाजपा की सरकार है लेकिन एसवाईएल पर निर्णय नहीं ले पा रहे। दक्षिण हरियाणा में पानी की बहुत कमी है, एसवाईएल बननी चाहिए, कोर्ट ने भी निर्णय दे रखा है। उन्होंने कहा कि बजट में न तो युवाओं के लिए रोजगार के ठोस अवसर दिखाई देते हैं और न ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई प्रभावी योजना सामने आई है। हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए बजट में कोई विशेष पैकेज या ठोस प्रावधान नहीं किया गया, जिससे किसानों, मजदूरों और ग्रामीण वर्ग में भारी निराशा है। खाद, बीज, डीजल और कृषि उपकरणों की बढ़ती कीमतों पर भी सरकार ने कोई राहत नहीं दी है।

ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जल्द जारी होगी : राव राव नरेंद्र सिंह ने संगठनात्मक स्थिति पर कहा कि हरियाणा में जिला संगठन का पुनर्गठन तेजी से किया जा रहा है। ब्लॉक अध्यक्षों की सूची जल्द जारी की जाएगी। इसके साथ संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का कार्य लगातार जारी है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुभाष गोयल, पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी, पूर्व बरवाला प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह गंगवा, वरिष्ठ नेता धर्मवीर गोयत, पूर्व चेयरमैन कृष्ण सिंगला उर्फ़ टीटू, जिलाध्यक्ष बृजलाल बहबलपुरिया, गायत्री यादव, प्रदेश प्रवक्ता योगेश सिहाग आदि उपस्थित रहे।

संपादकीय...

युवा जागो... नशे से नहीं, लक्ष्य से पहचान बनती है

आज का युवा ऊर्जा है, उम्मीद है, और देश का भविष्य है। वही युवा अगर सही दिशा में चले तो परिवार का सहारा बनता है, समाज का नेतृत्व करता है और देश की ताकत बनता है। लेकिन जब यही युवा नशे की गिरफ्त में फंस जाता है, तो वह सिर्फ अपना नहीं, अपने पूरे परिवार का भविष्य अंधकार में धकेल देता है।

नशा कभी किसी का साथी नहीं होता। शुरुआत में यह दोस्त जैसा लगता है, लेकिन धीरे-धीरे यह इंसान को उसकी पहचान, उसकी इज्जत, उसका आत्मसम्मान और उसके रिश्ते सब कुछ छीन लेता है। जो बेटा अपने माता-पिता की आंखों का तारा होता है, वही नशे की हालत में उनकी सबसे बड़ी चिंता बन जाता है। जो पति अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला होता है, वही नशे के कारण अपनी पत्नी और बच्चों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है।

आज जरूरत है कि युवा यह समझें कि जीवन बहुत कीमती है। माता-पिता ने जिस उम्मीद से उन्हें पाला है, वे सपने नशे की वजह से टूटने नहीं चाहिए। समाज भी उन्हीं युवाओं को सम्मान देता है जो मेहनत करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं और अपनी मेहनत से मुकाम हासिल करते हैं।

नशा समस्या का समाधान नहीं है, यह समस्या की जड़ है। असली सुकून मेहनत में है, सफलता में है, परिवार की मुस्कान में है। युवा अगर अपनी ऊर्जा को पढ़ाई, खेल, व्यवसाय, तकनीक और समाज सेवा में लगाएं तो वे खुद भी आगे बढ़ेंगे और समाज को भी आगे बढ़ाएंगे।

आज हर युवा को खुद से एक सवाल पूछना चाहिए—

क्या मैं अपने माता-पिता का गर्व बन रहा हूं या उनकी चिंता?

क्या मैं अपने बच्चों के लिए उदाहरण बनूंगा या चेतावनी?

समय आ गया है कि युवा नशे से दूरी बनाकर अपने सपनों के करीब जाएं। अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, और अपने भविष्य के लिए सही रास्ता चुनें।

याद रखिए—

नशा आपको कमजोर बनाता है, लक्ष्य आपको मजबूत बनाता है।

युवा जागिए, संभलिए और अपने जीवन को उस मुकाम तक पहुंचाइए जहां आपके माता-पिता गर्व से कह सकें—

"यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है।"

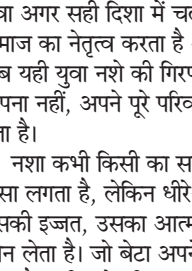

राहुल हिंदुस्तानी
संपादक
राजधानी चौपाल

खेजड़ी बचेगी तो राजस्थान बचेगा

29 संत, 80 महिलाएँ सहित 363 पर्यावरण प्रेमी आमरण अनशन पर –यह सिर्फ पेड़ नहीं, मरुस्थल की सांस है

बीकानेर की धरती इन दिनों एक बार फिर इतिहास लिख रही है। वही धरती, जहाँ कभी अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 29 संत, 80 महिलाएँ और कुल 363 पर्यावरण प्रेमी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनकी मांग साफ है—50 वर्ष से अधिक पुराने किसी भी खेजड़ी वृक्ष को न काटा जाए और सरकार तत्काल सख्त ट्री प्रोटेक्शन कानून लागू करे।

यह आंदोलन केवल पेड़ों के संरक्षण की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की आत्मा, उसकी संस्कृति, उसकी जलवायु और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व की लड़ाई है।

खेजड़ीः मरुस्थल की जीवनरेखा

खेजड़ी कोई साधारण पेड़ नहीं है। यह राजस्थान के रेगिस्तानी जीवन की रीढ़ है। यह पेड़ पशुओं का चारा देता है, जमीन की उर्वरता बढ़ाता है, गर्मी में छांव देता है, हवा को शुद्ध करता है और मरुस्थल में नमी बनाए रखने का काम करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार खेजड़ी आसपास के क्षेत्र का तापमान 2 से 3 डिग्री तक कम करने की क्षमता रखता है। जब प्रदेश में 19.60 लाख करोड़ रुपये के विकास प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, जब 30% क्षेत्र हरियाली बढ़ाने की योजनाओं की चर्चा हो रही है, तब खेजड़ी जैसे प्राकृतिक संरक्षक वृक्षों को काटना किस विकास की निशानी है?

सरकार से सीधा सवाल

आंदोलनकारियों का कहना है कि विकास के नाम पर सैकड़ों खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं। सड़क, भवन, वेयरहाउस, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स और कॉलोनियों के विस्तार में सबसे पहले निशाना बनती है खेजड़ी।

सवाल यह है : क्या विकास का रास्ता पेड़ों की लाशों से होकर ही जाएगा? यदि सरकार सच में पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर है, तो 50 साल पुराने खेजड़ी वृक्षों को "हेरिटेज ट्री" घोषित क्यों नहीं किया जाता? इनके संरक्षण के लिए अलग कानून क्यों नहीं लाया जाता?

महिलाओं और संतों की भागीदारीः यह चेतावनी है

इस आंदोलन में 80 महिलाओं और 29 संतों का शामिल होना यह दर्शाता है कि यह कोई राजनीतिक या औपचारिक विरोध नहीं, बल्कि जनआस्था और जनभावना का विस्फोट है। महिलाएँ, जो घर-परिवार और प्रकृति के संतुलन की असली संरक्षक होती हैं, जब सड़क पर बैठती हैं, तो समझ लेना चाहिए कि मामला गंभीर है। संतों का अनशन पर बैठना समाज को यह संदेश देता है कि यह आंदोलन धर्म, प्रकृति और जीवन के संरक्षण का संगम है।

इतिहास दोहराने की तैयारी

राजस्थान की पहचान "पेड़ से पहले प्राण" देने की रही है। खेजड़ी के लिए पहले भी बलिदान हुए हैं। आज फिर लोग उसी राह पर खड़े हैं। आंदोलनकारियों ने साफ कहा है—यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो इतिहास दोहराया जाएगा। क्या सरकार उस स्थिति का इंतजार कर रही है?

पर्यावरण प्रेमियों की प्रमुख मांगें

- 50 वर्ष से अधिक पुराने खेजड़ी वृक्षों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध
- ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को विधानसभा में तत्काल लाना
- जिन क्षेत्रों में खेजड़ी काटी गई है, वहाँ पुनः रोपण और संरक्षण
- विकास कार्यों के लिए वैकल्पिक डिजाइन, जिससे पेड़ बच सकें

यह सिर्फ बीकानेर की लड़ाई नहीं

आज बीकानेर में जो हो रहा है, वह कल पूरे राजस्थान का भविष्य तय करेगा। खेजड़ी बचेगी तो मरुस्थल में जीवन बचेगा। यदि खेजड़ी खत्म हुई, तो आने वाले वर्षों में तापमान, जल संकट और रेगिस्तान का फैलाव किस स्तर पर होगा, इसकी कल्पना भी भयावह है।

राजधानी सुपर की स्पष्ट राय

सरकार को इस आंदोलन को चेतावनी नहीं, अवसर के रूप में देखना चाहिए। यह मौका है राजस्थान को पर्यावरण संरक्षण में देश का मॉडल राज्य बनाने का। ट्री प्रोटेक्शन कानून लागू कर सरकार इतिहास में अपना नाम दर्ज कर सकती है।

यदि आज भी खेजड़ी नहीं बची, तो आने वाली पीढ़ियाँ पूछेंगी—

जब पेड़ बचाने वाले अनशन पर थे, तब सरकार क्या कर रही थी?

खेजड़ी केवल पेड़ नहीं... यह राजस्थान की सांस है।

और सांसों से समझौता कभी विकास नहीं कहलाता।

भारतीय सड़कों पर टाटा का नया इलेक्ट्रिक अवतार!

टाटा पंच EV फेसलिफ्ट 20 फरवरी को होगी लॉन्च; लग्जरी फीचर्स और 421KM की रेंज के साथ बदलेगी मिड-बजट सेगमेंट की तस्वीर

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल) | भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की क्रांति का नेतृत्व कर रही दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स एक बार फिर धमाका करने को तैयार है। देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली छोटी एसयूवी में से एक, 'टाटा पंच' अब अपने नए इलेक्ट्रिक अवतार में धूम मचाने आ रही है। कंपनी आगामी 20 फरवरी को टाटा पंच EV का 'फेसलिफ्ट' मॉडल लॉन्च करने जा रही है। जनवरी 2024 में अपनी पहली लॉन्चिंग के बाद से ही पंच EV ने मध्यम वर्ग के परिवारों के बीच अपनी खास जगह बनाई थी। अब, ठीक दो साल बाद, कंपनी इसमें कई ऐसे बड़े अपडेट दे रही है जो आमतौर पर केवल लग्जरी कारों में ही देखने को मिलते हैं। इस बदलाव का सीधा असर भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक कार मार्केट पर पड़ना तय माना जा रहा है।

डिजाइन में दिखा मॉडर्न टचः पेट्रोल वर्जन से प्रेरित लुक

नई टाटा पंच EV फेसलिफ्ट का बाहरी स्वरूप अब पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम और आकर्षक हो गया है। डिजाइन के मामले में इसे हाल ही में अपडेट हुए इसके पेट्रोल (ICE) मॉडल जैसा ही आधुनिक रूप दिया गया है।

- **फ्रंट प्रोफाइलः** इसके फ्रंट में अब आपको नए डिजाइन की ग्रिल और पूरी तरह से कनेक्टेड LED DRLS देखने को मिलेंगे। यह हेडलाइट सेटअप इसे टाटा की बड़ी कारों (जैसे हैरियर और सफारी) जैसा लुक देता है।
- **रियर प्रोफाइलः** पीछे की तरफ सबसे बड़ा बदलाव 'कनेक्टेड LED टेललाइट्स' के रूप में हुआ है। जब ये लाइटें जलती हैं, तो कार की चौड़ाई और उसकी रोड प्रेजेंस काफी प्रभावशाली नजर आती है। इसके बंपर को भी नया फिनिश दिया गया है जो पहले से अधिक मजबूत दिखता है।
- **साइड प्रोफाइलः** कंपनी ने इसमें नए 'एरोडायनामिक अलॉय व्हील्स' लगाए हैं। ये केवल देखने में ही सुंदर नहीं हैं, बल्कि ये हवा के दबाव को कम करते हैं, जिससे बैटरी की रेंज बढ़ाने में मदद मिलती है।

इंटीरियरः टेक्नोलॉजी और आराम का बेजोड़ संगम

कार के केबिन में घुसते ही आपको एक हाई-टेक लग्जरी अहसास होगा। टाटा ने इसके इंटीरियर को पूरी तरह से री-डिजाइन किया है ताकि ग्राहकों को एक 'स्मार्ट केबिन' का अनुभव मिल सके।

- **बड़ी स्क्रीनः** अब इसमें 12.3 इंच का विशाल टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा। यह स्क्रीन इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन स्क्रीन्स में से एक मानी जा रही है।
- **वेंटिलेटेड सीट्सः** भारतीय गर्मियों को ध्यान में रखते हुए, टाटा ने पहली बार इस बजट सेगमेंट में वेंटिलेटेड सीट्स (ठंडी हवा देने वाली सीटें) का फीचर दिया है, जो लंबी यात्राओं को थकान मुक्त बनाता है।
- **नया स्टीयरिंग व्हीलः** नई सफारी की तरह, इसमें भी टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जिसके बीच में टाटा का लोगो अंधेरे में भी चमकता (ILLUMINATED) नजर आएगा। साथ ही, इलेक्ट्रिक सनरूफ इसे और भी भव्य बनाती है।

रफ़्तार और रेंज का 'पावरहाउस': एक चार्ज में दिल्ली से भी दूर का सफर!

टाटा पंच EV के मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह शहर की भीड़भाड़ और हाईवे की रफ़्तार, दोनों में खरी उतरती है। इसमें ग्राहकों को दो खास बैटरी विकल्प दिए गए हैं:

- **मिड रेंज और लॉन्ग रेंज का दम :** मिड रेंज (25KWH): यह मॉडल उन लोगों के लिए है जिनका शहर के अंदर ज्यादा सफर रहता है। यह एक बार फुल चार्ज होने पर 315 किलोमीटर की रेंज देती है। इसमें 80BHP की पावर और 114NM का टॉर्क मिलता है, जिसे 3.3KW AC चार्जर से चार्ज किया जा सकता है।
- **लॉन्ग रेंज (35kWh):** लंबी दूरी तय करने वालों के लिए यह मॉडल बेहतरीन है। इसकी रेंज 421 किलोमीटर तक जाती है। इसमें 120BHP की जबरदस्त पावर और 190NM का टॉर्क मिलता है। खास बात यह है कि इसमें 50KW DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जो सफर के दौरान कार को बहुत जल्दी चार्ज कर देता है।
- **रफ़्तार ऐसी कि पलक झपकते ही 100 पार!**

नई पंच EV केवल बैटरी बचाने के लिए नहीं बनी, बल्कि इसमें रफ़्तार का भी जबरदस्त रोमांच है। यह इलेक्ट्रिक SUV मात्र 9.5 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ लेती है। इसकी 140 KMPH की अधिकतम रफ़्तार (TOP SPEED) इसे हाईवे का 'छोटा रॉकेट' बनाती है, जिससे ओवरटेकिंग करना बेहद आसान और सुरक्षित हो जाता है।

सुरक्षा में कोई समझौता नहीं (ADAS सेफ्टी)

टाटा मोटर्स की पहचान उनकी कारों की मजबूती से होती है, और नई पंच EV इस मामले में एक कदम और आगे निकल गई है:

- ADAS **टेक्नोलॉजीः** पंच EV फेसलिफ्ट में पहली बार ADAS (ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEM) फीचर दिया जा सकता है। इसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट जैसे सेंसर-आधारित सुरक्षा फीचर्स होंगे।
- **360° कैमराः** तंग गलियों में पार्किंग को आसान बनाने के लिए इसमें 360-डिग्री कैमरा दिया गया है।
- **मानक सुरक्षाः** सभी मॉडल्स में 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे फीचर्स को स्टैंडर्ड (अनिवार्य) रखा गया है।

ऑटो विशेषज्ञों के अनुसार, नई टाटा पंच EV फेसलिफ्ट की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 15 लाख तक जा सकती है। मिड-बजट इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में यह कार फिलहाल किंग की भूमिका में है। इसका मुकाबला सिट्रोएन EC3 और आने वाली एमजी (MG) की किफायती इलेक्ट्रिक कारों से होगा।

पहली सरकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी लॉन्च : ओला-उबर की तरह ड्राइवर को कमीशन नहीं देना होगा, पीक आवर में किराया नहीं बढ़ेगा

हिसार (राजधानी चौपाल)| देश की पहली सहकारी कैब टैक्सी सर्विस 'भारत टैक्सी' आज से दिल्ली और गुजरात के कुछ शहरों में शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में इस एप को लॉन्च किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि, 'सर्विस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ड्राइवरों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा और वे खुद इस प्लेटफॉर्म के हिस्सेदार या मालिक होंगे। इसके अलावा, पीक आवर्स में यूजर्स को सर्ज प्राइस (ज्यादा किराया) भी नहीं देना होगा। भारत टैक्सी' का उद्देश्य ड्राइवरों को निजी एग्रीगेटर कंपनियों के मॉडल से आजादी दिलाना है।' टैक्सी का ट्रायल 2 दिसंबर को दिल्ली और गुजरात के राजकोट में शुरू किया गया था, जो सफल रहा है।

रिटायरमेंट सेविंग्स और ड्राइवर सपोर्ट सिस्टम मिलेगा : लॉन्चिंग के दौरान अमित शाह एप के ट्रायल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 6 ड्राइवर्स (जिन्हें 'सारथी' कहा गया है) को सम्मानित किया। इन ड्राइवर्स को कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट बांटे गए। सम्मानित होने वाले ड्राइवर्स को 5 लाख रुपए का एक्सिडेंटल और 5 लाख रुपए का फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया गया। इसके अलावा, प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले सभी ड्राइवर्स के लिए रिटायरमेंट सेविंग्स और ड्राइवर सपोर्ट सिस्टम जैसी सुविधाएं भी जोड़ी गईं।

जीरो कमीशन और सर्ज-प्राइसिंग से राहत मिलेगी : निजी कंपनियां जैसे ओला और उबर आमतौर पर ड्राइवरों की कमाई से 20% से 30% तक कमीशन वसूलती हैं। इसके उलट, भारत टैक्सी 'जीरो-कमीशन' मॉडल पर काम करेगी। यानी ड्राइवर जितनी कमाई करेगा, वह सीधे उसके पास जाएगी। इसके साथ ही, ग्राहकों के लिए भी राहत की बात यह है कि इसमें 'सर्ज-प्राइसिंग' (पीक ऑवर्स में ज्यादा किराया) का सिस्टम नहीं होगा। इससे यात्रियों को भी किफायती दरों पर टैक्सी मिल सकेगी।

अगले 2 साल में हर शहर तक पहुंचने का टारगेट : भारत टैक्सी को अगले दो साल में देश के सभी राज्यों और प्रमुख शहरों में शुरू करने का टारगेट है। इसके लिए सरकार के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के साथ इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। दिल्ली के 7 प्रमुख स्थानों पर ड्राइवरों के लिए सपोर्ट सेंटर भी शुरू किए गए हैं।

भारत टैक्सी को कौन चलाएगा : यह सदस्यता आधारित मॉडल है, जिसे सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड चलाएगा। इसकी स्थापना जून में 300 करोड़ की रकम के साथ हुई। एप आधारित यह सेवा डिजिटल इंडिया का हिस्सा है। इसकी एक संचालन परिषद होगी, जिसमें अमूल के एमडी जयेन मेहता चेयरमैन और एनसीडीसी के उप प्रबंधक निदेशक रोहित गुप्ता वाइस चेयरमैन हैं। इसके अलावा 8 अन्य सदस्य भी हैं, जो देश की विभिन्न सहकारी समितियों से जुड़े हैं। इस बोर्ड की पहली बैठक 16 अक्टूबर को हो चुकी है।

4 सवाल-जवाब में भारत टैक्सी के फायदे समझिए...

Q.1. इसकी सर्विस कैसे ले सकेंगे?
भारत टैक्सी का एप ओला-उबर जैसा होगा, जो नवंबर में एप स्टोर्स से डाउनलोड कर सकेंगे। एप हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी में होगा।

Q.2. ड्राइवरों को क्या फायदा होगा?
हर राइड की 100% कमाई ड्राइवर को मिलेगी। उसे सिर्फ दैनिक, साप्ताहिक या मासिक शुल्क देना होगा, जो कि बहुत ही सामान्य रहेगा।

Q.3. महिला सारथी की क्या भूमिका रहेगी?
यानी महिला ड्राइवर्स। पहले चरण में 100 महिलाएं जुड़ेंगी। 2030 तक इनकी संख्या 15 हजार करेंगे। 15 नवंबर से मुफ्त प्रशिक्षण, विशेष बीमा मिलेगा।

Q. 4. यह सेवा 2030 तक कैसे आगे बढ़ेगी?
दिसंबर से मार्च 2026 तक राजकोट, मुंबई, पुणे में सर्विस। ड्राइवर 5 हजार होंगे। मल्टी स्टेट ऑपरेशन। अप्रैल से दिसंबर के बीच लखनऊ, भोपाल, जयपुर में शुरुआत होगी। 15 हजार ड्राइवर और 10 हजार गाड़ियां हो जाएंगी। 2027-28 में 20 शहरों में 50 हजार ड्राइवर्स के साथ पैन इंडिया सर्विस मिलने लगेगी। इसे फास्टैग से जोड़ेंगे। 2028-2030 के बीच जिला मुख्यालयों, गांवों में एक लाख ड्राइवरों के साथ सेवा शुरू होगी।

न्यूज ब्रीफ

सैमसंग गैलेक्सी F70E भारत में लॉन्च होगा : लैदर फिनिश डिजाइन के साथ 50MP कैमरा

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल) | सैमसंग इंडिया 9 फरवरी को भारत में F सीरीज में नया स्मार्टफोन गैलेक्सी F70E लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने गैलेक्सी F70E की ईमेज और स्पेसिफिकेशन्स शेयर कर दिए हैं। नया गैलेक्सी स्मार्टफोन 6000MAH बैटरी, 6.7-इंच का HD+ और 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर के साथ आएगा। यह लो बजट स्मार्टफोन होगा, जिसकी कीमत 15 से 18 हजार रुपए के बीच रखी जा सकती है। उम्मीद है नया फोन गैलेक्सी F07E अगले हफ्ते बिक्री के लिए अवेलेबल हो जाएगा।

नए सैमसंग फोन का बैक पैनल लैदर फिनिश के साथ आएगा, जो प्रीमियम और सॉफ्ट फील देगा। यह डिजाइन इसे उंगलियों के निशान और छोटे-मोटे स्क्रैच से भी बचाता है। कंपनी इसे दो कलर ऑप्शन- लाइमलाइट ग्रीन और स्पॉटलाइट ब्लू के साथ पेश करेगी। सामने की तरफ 6.7 इंच की बड़ी स्क्रीन है, जिसमें पतले बेजल्स हैं। फोन में टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और जरूरी बटन दिए गए हैं। इस सैमसंग स्मार्टफोन को IP54 रेटिंग के साथ पेश किया जाएगा जो पानी की बौछारों से बचाने में मदद करेगा।

डिस्प्लेः सैमसंग गैलेक्सी F70E में कंपनी ने 1600 X 720 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली 6.7-इंच की HD+ स्क्रीन दी है। यह इनफिनिटी 'यू' वॉटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले है, जो LCD पैनल पर बनी है। इसमें 120HZ रिफ्रेश रेट के साथ 800 निट्स पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट भी मिलेगा।

कैमराः फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक पैनल पर डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। इसमें LED फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल मेन सेंसर और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर शामिल होगा। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है।

बैटरीः सैमसंग गैलैक्सी F70E में पावर बैकअप के लिए 6,000MAH की बैटरी दी जाएगी। सैमसंग के मुताबिक यह भारी इस्तेमाल के बावजूद आसानी से 2 दिन तक चल सकती है। बैटरी चार्ज करने के लिए फोन में 25W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है।

परफॉर्मेंसः फोन को मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जाएगा। यह 6 नैनोमीटर फेब्रिकेशन्स पर बना मोबाइल चिपसेट है, जो 2.0GHZ से लेकर 2.4GHZ तक की क्लॉक स्पीड पर रन कर सकता है।

रियलमी P4 सीरीज के स्मार्टफोन 4 हजार तक महंगे हुए : 50MP कैमरा के साथ

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल) | टेक कंपनी रियलमी इंडिया ने अपने मिड रेंज रियलमी P4 सीरीज के 5G स्मार्टफोन्स P4 और P4 प्रो की कीमत में बढ़ा दी हैं। रियलमी P4 की कीमत में जहां 2,500 रुपए की बढ़ोतरी की गई गई है। वहीं रियलमी P4 प्रो के दाम 4,000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। दोनों फोन 7000MAH बैटरी के साथ आते हैं, इनमें 50MP कैमरा और 144HZ रिफ्रेश रेट वाली 4D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है।

डिजाइनः मेटालिक फ्रेम के साथ प्रीमियम नेचुरल टेक्सचर : रियलमी P4 में मेटालिक और प्लास्टिक फिनिश दिया गया है। इसमें मेटालिक लाइन्स और एक्सपोज्ड स्क्रू डिटेल्स हैं, जो इसे मजबूत और स्टाइलिश बनाते हैं। इसमें 6.77 इंच का डिस्प्ले है और इसके बेजल्स काफी पतले हैं। डिजाइन में फ्लैट फ्रेम्स और स्लिम बैक पैनल का इस्तेमाल किया गया है। रियलमी P4 को IP65+IP66 रेटिंग के साथ पेश किया गया है। इसका वजन लगभग 194 ग्राम और मोटाई 7.58MM है। इसके बैक पैनल पर डुअल रियर कैमरा सेटअप है, कैमरा मॉड्यूल काफी पतला है। फोन तीन बोल्ड कलर ऑप्शन- स्टील ग्रे, इंजन ब्लू, और फोर्ज रेड में अवेलेबल है। वहीं, रियलमी P4 प्रो में टेक-वुड मटेरियल के साथ प्रीमियम और नेचुरल टेक्सचर वाला डिजाइन दिया गया है। मेटालिक फ्रेम के साथ बैक पैनल मैट टेक्सचर दिया गया है, जो फिंगरप्रिंट्स को कम करता है। इसमें 6.8-इंच का डिस्प्ले है, जिसके बेजल्स काफी पतले हैं। फोन का वजन लगभग 189-194 ग्राम है और मोटाई 7.68-7.69MM है। कैमरा मॉड्यूल एक सर्कुलर आइलैंड डिजाइन में है, जो ज्यादा बाहर नहीं निकलता और फोन को सपाट सतह पर स्थिर रखता है। LED फ्लैश को कैमरा सेंसर से अलग रखा गया है। ये फोन भी तीन कलर ऑप्शन- बर्च वुड, डार्क ओक वुड और मिडनाइट आइवी के साथ आया है।

सैमसंग प्रीमियम गैलेक्सी S26 सीरीज लाएगी; वीवो, रियलमी और पोको जैसे ब्रांड भी पेश करेंगे फोन

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल) | स्मार्टफोन लवर्स के लिए फरवरी का महीना बेहद खास होने वाला है। इस महीने सैमसंग अपनी सबसे प्रीमियम नेक्स्ट जनरेशन गैलेक्सी S26 सीरीज लॉन्च करेगी। इसके साथ ही वीवो, रियलमी, पोको और मोटोरोला जैसे बड़े ब्रांड्स भी अपने नए फोन बाजार में उतारने की तैयारी में हैं। इस महीने बजट फोन से लेकर पावरफुल फ्लैगशिप डिवाइसेज तक 14 से ज्यादा नए स्मार्टफोन आएंगे। इनमें 9000MAH जैसी बड़ी बैटरी और 200MP कैमरे जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। आईक्यू 15 अल्ट्रा स्मार्टफोन 4 फरवरी 2026 को चीन में लॉन्च होगा इसके बाद यह भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा। यह वीवो के सब-ब्रांड आईक्यू का पहला 'अल्ट्रा' फोन होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फोन में 6.85 इंच की बड़ी फ्लैट स्क्रीन होगी, जो सैमसंग की LTPO टेक्नोलॉजी वाली होगी और 2K क्वालिटी की पिक्चर देगी। परफॉर्मेंस के लिए इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 प्रोसेसर होगा। साथ में 24GB तक रैम और 1TB तक स्टोरेज मिल सकती है। फोन में 100W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7400MAH की बड़ी बैटरी मिलेगी। कैमरा की बात करें तो रियर में 50-50 मेगापिक्सल के 3 कैमरे होंगे। इनमें से एक टेलीफोटो कैमरा 3X तक ऑप्टिकल जूम देगा और अच्छी स्टेबलाइजेशन के साथ आएगा, ताकि फोटो ब्लर न हों। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा।

होंडा शाइन 125 लिमिटेड एडिशन भारत में लॉन्च

नए डिजाइन ग्राफिक्स के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन जैसे फीचर्स

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल) | होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपनी सबसे पॉपुलर बाइक में से एक शाइन 125 का लिमिटेड एडिशन भारत में लॉन्च किया है। यह नया वैरिएंट शाइन 125 के 'डिस्क' मॉडल पर बेस्ड है। कंपनी ने इसे स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में ज्यादा प्रीमियम बनाने के लिए कई कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं।

- **बाइक दो वैरिएंट**- ड्रम और डिस्क में अवेलेबल है। ड्रम वैरिएंट की कीमत 84,493 रुपए और डिस्क वैरिएंट की प्राइस 89,245 रुपए (एक्स-शोरूम दिल्ली) रखी गई है। खास बात यह है कि यह अपने स्टैंडर्ड डिस्क वैरिएंट की तुलना में सिर्फ 1,000 रुपए महंगी है।

होंडा शाइन 125 में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन जैसे फीचर्स दिए गए हैं। 125CC कम्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट में इसका मुकाबला हीरो ग्लैमर एक्सटैक, हीरो सुपर स्प्लेंडर, TVS राइडर से है।

डिजाइनः नए ग्राफिक्स और कलरफुल अलॉय व्हील्स

लिमिटेड एडिशन में मुख्य बदलाव इसके लुक में किए गए हैं-

- **टैंक ग्राफिक्सः** फ्यूल टैंक पर दिए गए 'SHINE' ग्राफिक्स को रिवाइज किया गया है, जो अब पहले से ज्यादा बोल्ड दिखते हैं।
- **अलॉय व्हील्सः** बाइक का सबसे बड़ा हाइलाइट इसमें पाइराइट ब्राउन कलर के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसके बॉडी कलर को अच्छा कॉन्ट्रास्ट देते हैं और नए डेकल्स भी हैं।
- **क्रोम फिनिशः** हेडलाइट के चारों ओर क्रोम ट्रिम, साइड पैनल और एग्जॉस्ट (साइलेंसर) कवर पर क्रोम का काम पहले की तरह ही है।
- **कलर ऑप्शनः** यह लिमिटेड एडिशन 'पर्ल सायरन ब्लू' कलर में उपलब्ध होगा, जो स्टैंडर्ड बाइक में भी मिलता है। बाइक में एक लंबी सिंगल-पीस सीट है, जिसके अंत में बॉडी-कलर ग्रैब रेल है।
- **परफॉर्मेंसः** स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम के साथ 123.94CC सिंगल-सिलेंडर इंजन

नई होंडा शाइन 125 में परफॉर्मेंस के लिए अब 123.94CC सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, OBD2B कंप्लायंट इंजन है, जो 10.63HP की पावर और 11NM का टॉर्क जनरेट करता है और ट्रांसमिशन के लिए इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ ट्यून किया गया है।

बाइक में होंडा का आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम भी है, जो बाइक को खड़े रहने पर बंद कर देता है और थ्रॉटल के घुमाव पर इसे फिर से स्टार्ट करता है। इससे माइलेज बेहतर होता है। इसमें साइलेंट इग्निशन के लिए ACG (अल्टरनेटिंग करंट जेनरेटर) स्टार्टर भी है।

सिंगल चैनल ABS वाला पहला स्कूटर सुजुकी एक्सेस 125 लॉन्च

नेविगेशन और कॉल अलर्ट के लिए डिजिटल TFT डिस्प्ले, शुरुआती कीमत 92 हजार

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल) | सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले स्कूटर 'एक्सेस 125' को नए सेफ्टी फीचर अपडेट के साथ लॉन्च कर दिया है। स्कूटर में अब सिंगल-चैनल एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) दिया जाएगा। इससे गीली सड़कों या इमरजेंसी में अचानक ब्रेक लगाने पर टायर लॉक होने और फिसलने का खतरा कम हो जाएगा।

इसके साथ ही यह भारत में सिंगल चैनल ABS वाला पहला 125CC स्कूटर बन गया है। नया ABS मॉडल दो वैरिएंट्स- राइड कनेक्ट और राइड कनेक्ट TFT में अवेलेबल होगा। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 92,328 रुपए है। ये स्टैंडर्ड मॉडल से 4,500 तक महंगा हो गया है। खास बात ये है कि स्कूटर के ABS वैरिएंट्स में किक-स्टार्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिलेगा।

150cc स्कूटर्स को देगा टक्कर

अभी तक भारतीय बाजार में ABS का फीचर केवल 150CC या उससे ज्यादा पावर वाले स्कूटर्स जैसे TVS टॉर्क 150, अप्रीलिया SR 175 और यामाहा एरोक्स 155 में ही देखने को मिलता था। सरकारी नियमों के अनुसार 150CC से ऊपर की बाइक्स और स्कूटर्स में ABS अनिवार्य है, लेकिन सुजुकी इसे 125CC सेगमेंट में पेश कर नई शुरुआत की है।

डिजाइनः कंफर्ट के साथ मॉडर्न लुक

डिजाइन के मामले में भी एक्सेस 125 में कोई कॉस्मेटिक बदलाव नहीं हैं। इसमें क्लासिक रेट्रो लुक के साथ क्रोम फिनिश वाली LED हेडलाइट दी गई है। हार्डवेयर की बात करें तो फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में स्विंग आर्म मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है।

अब फ्रंट डिस्क ब्रेक के साथ ABS यूनिट को जोड़ा गया है, जबकि पीछे ड्रम ब्रेक ही मिलते हैं। स्कूटर में 12-इंच के फ्रंट और 10-इंच के रियर अलॉय व्हील्स लगे हैं, जो ट्यूबलेस टायरों के साथ आते हैं।

परफॉर्मेंसः इंजन और पावर में कोई बदलाव नहीं

स्कूटर में कोई भी मैकेनिकली बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले की तरह ही 124CC का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है। यह 6750RPM पर 8.4HP की पावर और 5500RPM पर 10.2NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है। स्मूथ राइडिंग के लिए इसमें CVT गियरबॉक्स दिया गया है। इसके टॉप वैरिएंट में 4.2-इंच का फुल-कलर TFT डिस्प्ले मिलता है, जो 'सुजुकी राइड कनेक्ट' फीचर के साथ आता है। इसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को स्कूटर से कनेक्ट कर सकते हैं।

गूगल ला रहा सस्ता AI फोन पिक्सल 10a : फ्लैट कैमरे वाला नया डिजाइन

मुंबई (राजधानी चौपाल) | गूगल ने अपने किफायती स्मार्टफोन पिक्सल 10A की लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने एक यूट्यूब वीडियो में बताया कि नया AI-पावर्ड फोन 18 फरवरी को पेश किया जाएगा।

यह पिक्सल 10 सीरीज का सबसे सस्ता मॉडल होगा, जिसे कम कीमत में प्रीमियम AI फीचर्स देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह लॉन्चिंग एपल के नए किफायती आईफोन 17E के संभावित ऐलान से कुछ हफ्ते पहले हो रही है, जिसे ऐपल मार्च में पेश कर सकता है।

गूगल की ओर से जारी टीजर वीडियो में डिजाइन की झलक मिली है। फोन का लुक काफी हद तक पुराने मॉडल जैसा ही है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव इसके कैमरा सेटअप में है।

इस बार गूगल ने 'फ्लश' डिजाइन दिया है, यानी फोन के पीछे कैमरा सेटअप बिल्कुल सपाट होगा। पिछले मॉडल पिक्सल 9A में कैमरे के चारों ओर एक उभरी हुई पट्टी दी गई थी।

सस्ते फोन में प्रीमियम AI फीचर्स मिलेंगे : पिक्सल A-सीरीज गूगल के लिए काफी अहम है क्योंकि यह कम बजट वाले ग्राहकों को पिक्सल इकोसिस्टम से जोड़ती है। पिक्सल 10A में गूगल के लेटेस्ट जेमिनी फीचर्स का सपोर्ट मिलेगा। गूगल के ये AI फीचर्स ऐपल के 'ऐपल इंटेलिजेंस' के मुकाबले ज्यादा एडवांस माने जाते हैं।

जेमिनी लाइवः यूजर फोन से इंसान की तरह बातचीत कर सकेंगे।

सर्कल टू सर्चः किसी भी फोटो या वीडियो पर गोला बनाकर सर्च।

एपल और सैमसंग से पहले लॉन्चिंग की तैयारी : गूगल ने पिक्सल 10A की लॉन्चिंग के लिए फरवरी का समय चुना है, क्योंकि मार्च में एपल अपना सस्ता आईफोन 17E लॉन्च कर सकता है। वहीं सैमसंग भी अपनी गैलेक्सी S26 सीरीज लाने वाला है। ये सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज है। गूगल चाहता है कि इन बड़े ब्रांड्स के आने से पहले वह भारत, जापान और अमेरिका जैसे बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत कर ले। भारत जैसे देश में, जहां लोग कम कीमत में प्रीमियम अनुभव चाहते हैं, वहां पिक्सल 10A गूगल की मार्केट हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार गूगल कीमत थोड़ी बढ़ा सकता है। मोबाइल इंडस्ट्री में रैम और अन्य हार्डवेयर पार्ट्स की कीमतें बढ़ने की वजह से स्मार्टफोन कंपनियों पर दाम बढ़ाने का दबाव है। हालांकि, गूगल ने अभी तक आधिकारिक कीमत का खुलासा नहीं किया है।

क्या है पिक्सल A-सीरीज : गूगल हर साल अपनी फ्लैगशिप सीरीज के कुछ महीनों बाद एक 'A' वर्जन लॉन्च करता है। इसमें प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर वही होते हैं जो महंगे पिक्सल फोन में मिलते हैं, लेकिन बॉडी मटेरियल और कुछ कैमरा फीचर्स में कटौती करके इसकी कीमत कम रखी जाती है।

आज के आधुनिक युग में कपड़ों का चयन केवल शरीर ढकने तक सीमित नहीं रह गया है। यह हमारे व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति का प्रतीक बन चुका है। इसी फैशन की अंधी दौड़ में 'स्किनी जीन्स' और 'अल्ट्रा-टाइट फिटिंग' के कपड़े युवाओं की पहली पसंद बन गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस टाइट जीन्स को पहनकर आप शीशे के सामने खुद को स्टाइलिश महसूस करते हैं, वही जीन्स आपके शरीर के भीतर कई गंभीर बीमारियों का जाल बुन रही है?

क्या आपकी पसंदीदा फिटिंग जीन्स आपकी जान की दुश्मन बन रही है?

सेहत ही असली धन है। अगर हम केवल दिखने के लिए अपने अंगों को कष्ट दे रहे हैं, तो यह बुद्धिमानी नहीं है। डॉ. शिवराम और 'राजधानी चौपाल' की टीम का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि उन खतरों से आगाह करना है जिन्हें हम अनजाने में नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी वार्डरोब बदलें, अपनी सेहत बचाएं।

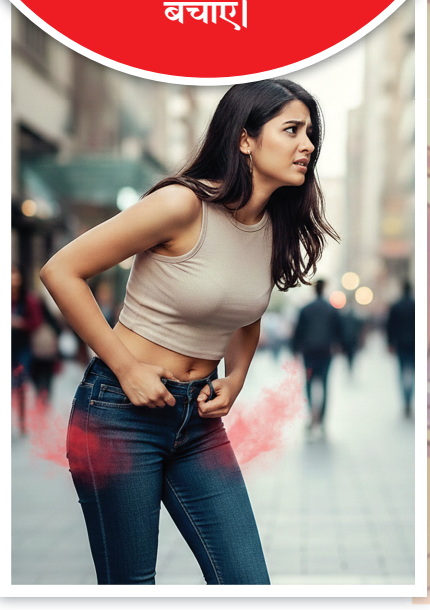

हाल ही में विश्व प्रसिद्ध चिकित्सा पत्रिका 'अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ' में प्रकाशित एक शोध और जयपुर स्थित अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉ. शिवराम की चेतावनियों ने फैशन जगत और आम जनता के बीच हड़कंप मचा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि टाइट जीन्स केवल एक कपड़ा नहीं, बल्कि शरीर के लिए एक 'संकुचन यंत्र' की तरह काम करती है, जो नसों, अंगों और यहाँ तक कि प्रजनन क्षमता को भी स्थायी रूप से नष्ट कर सकती है।

1. स्किनी जीन्स सिंड्रोमः जब नसें हार मान लेती हैं

चिकित्सा जगत में इन दिनों एक नया शब्द चर्चा में है— 'स्किनी जीन्स सिंड्रोम'। वास्तव में यह कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि टाइट कपड़ों के कारण होने वाले कई शारीरिक विकारों का एक समूह है।

डॉ. शिवराम बताते हैं कि जब हम बहुत टाइट जीन्स पहनते हैं, तो यह हमारी जांघों के ऊपरी हिस्से से गुजरने वाली मुख्य नसों पर भारी दबाव डालती है। इसे चिकित्सकीय भाषा में 'मेरालजिया पैरेस्थेटिका' कहा जाता है। इस स्थिति में पैरों में अचानक झनझनाहट होना, सुन्न पड़ जाना या तेज जलन महसूस होना आम बात है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 से 10 घंटे ऐसी टाइट जीन्स पहनकर बैठता है या चलता है, तो उसकी नसों में रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है, जिससे भविष्य में नर्व डैमेज (नसों का सूखना) का खतरा बढ़ जाता है।

टाइट जीन्स से होने वाले 7 भयानक दुष्प्रभाव

1. नसों पर दबाव (Nerve Compression): जांघों की नसों के दबने से पैरों में हमेशा के लिए सुन्नपन आ सकता है।

2. प्रजनन क्षमता में कमी: पुरुषों के अंडकोष का तापमान बढ़ने से शुक्राणुओं की संख्या (Sperm Count) तेजी से गिरती है।

3. किडनी पर खतरा: बार-बार होने वाले यूरिनरी इन्फेक्शन (UTI) के कारण संक्रमण किडनी तक पहुँच सकता है।

4. पाचन तंत्र का बिगड़ना: पेट पर अत्यधिक दबाव के कारण एसिडिटी और गंभीर कब्ज की समस्या होती है।

5. त्वचा के रोग: पसीने के न सूखने के कारण फंगल इन्फेक्शन, दाद और यीस्ट इन्फेक्शन का खतरा।

6. ब्लड सर्कुलेशन में बाधा: पैरों से वापस दिल की ओर जाने वाले खून की गति धीमी पड़ जाती है, जिससे थकान और सूजन होती है।

7. पीठ और घुटनों का दर्द: शरीर की प्राकृतिक मूवमेंट रुकने से मांसपेशियों में अकड़न और लोअर बैक पेन बढ़ जाता है।

2. मेल इनफर्टिलिटीः पुरुषों के लिए खतरे की घंटी

यह खबर उन पुरुषों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अपनी लाइफस्टाइल को लेकर सजग हैं। विज्ञान कहता है कि पुरुषों के टेस्टिकल्स (वृषण) शरीर के बाहर इसलिए होते हैं ताकि उनका तापमान शरीर के मुख्य तापमान से 2-3 डिग्री कम रह सके। यह कम तापमान स्वस्थ शुक्राणुओं के निर्माण के लिए अनिवार्य है।

जब कोई पुरुष टाइट जीन्स पहनता है, तो अंडकोष शरीर के एकदम करीब दब जाते हैं और वहां हवा का आवागमन बंद हो जाता है। इससे वहां का तापमान बढ़ जाता है। लंबे समय तक बढ़ा हुआ तापमान स्पर्म काउंट को कम कर देता है और शुक्राणुओं की तैरने की क्षमता (Motility) को खत्म कर देता है।

यूरोलॉजिस्ट की मानें तो आज के समय में बढ़ते पुरुष बांझपन के पीछे एक बड़ा कारण टाइट अंडरवियर और स्किनी जीन्स का फैशन है।

3. महिलाओं की वजाइनल हेल्थ और UTI का संकट

महिलाओं के लिए टाइट जीन्स पहनना एक अलग तरह की चुनौती और स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। महिलाओं का प्राइवेट एरिया बेहद संवेदनशील होता है और वहां नमी का बने रहना कई बीमारियों को निमंत्रण देता है।

अध्ययनों के अनुसार, टाइट कपड़े पहनने से वहां एयर-फ्लो (हवा का संचार) शून्य हो जाता है। इसके कारण पसीना जमा होता है, जो बैक्टीरिया और फंगस के पनपने के लिए स्वर्ग जैसा माहौल बनाता है। इसके परिणामस्वरूपः

- **यीस्ट इन्फेक्शनः** खुजली, जलन और सफेद पानी की समस्या।
- **यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (UTI):** बैक्टीरिया यूरिन मार्ग के जरिए भीतर प्रवेश कर जाते हैं।
- **किडनी डैमेजः** डॉ. शिवराम आगाह करते हैं कि यदि बार-बार UTI हो रहा है और महिला लगातार टाइट कपड़े पहन रही है, तो यह संक्रमण किडनी तक फैलकर उसे स्थायी रूप से डैमेज कर सकता है।

इन लोगों को तो 'ना' ही कह देना चाहिए टाइट जीन्स को

विशेषज्ञों के अनुसार, निम्नलिखित लोगों के लिए टाइट जीन्स पहनना किसी 'मेडिकल सुसाइड' से कम नहीं है:

- **ऑफिस जाने वाले लोगः** जो 8-9 घंटे लगातार कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं।
- **पेट के रोगीः** जिन्हें गैस, एसिड रिफ्लक्स या बार-बार पेट फूलने (BLOATING) की समस्या रहती है।
- **गर्भवती महिलाएंः** गर्भावस्था के दौरान टाइट कपड़े रक्त संचार रोककर शिशु के विकास में बाधा डाल सकते हैं।
- **भारी वजन वाले व्यक्तिः** मोटापा और टाइट कपड़ों का कॉम्बिनेशन नसों को बहुत जल्दी डैमेज करता है।
- **जिम जाने वाले एथलीटः** एक्सरसाइज के बाद मांसपेशियों को फैलने के लिए जगह चाहिए, जो टाइट जीन्स नहीं देती।
- **बैक पेन के मरीजः** जिन्हें स्लिप डिस्क या कमर दर्द की पुरानी बीमारी है।

पाचन और बैक पेनः अनसुनी समस्याएं

क्या आपने कभी गौर किया है कि भारी भोजन करने के बाद जब आप टाइट जीन्स पहनते हैं, तो आपको बेचैनी और सीने में जलन क्यों होती है? इसका कारण है पेट पर पड़ने वाला दबाव। जब आप टाइट जीन्स पहनकर बैठते हैं, तो वह आपके पेट के निचले हिस्से को दबाती है। इससे भोजन पचाने वाला एसिड ऊपर की ओर (Esophagus) आने लगता है। इसे 'एसिड रिफ्लक्स' कहते हैं।

इसके अलावा, टाइट जीन्स आपके कूल्हों और घुटनों की हड्डियों के मूवमेंट को जकड़ लेती है। जब आप चलते हैं या झुकते हैं, तो आपका शरीर स्वाभाविक रूप से नहीं मुड़ पाता, जिससे सारा तनाव आपकी निचली पीठ (Lower Back) पर आ जाता है। यही कारण है कि आज की युवा पीढ़ी में कमर दर्द और घुटनों की जकड़न के मामले बढ़ रहे हैं।

5. समाधान क्या है?

हम यह नहीं कहते कि आप फैशन छोड़ दें, लेकिन फैशन आपकी सेहत की कीमत पर नहीं होना चाहिए। विशेषज्ञों की इन सलाहों पर गौर करें:

- **फैब्रिक का चुनावः** हमेशा ऐसे कपड़े चुनें जो स्ट्रेचेबल हों और जिनमें हवा पास हो सके (जैसे कॉटन मिक्स)।
- **सही साइजः** हमेशा एक साइज ढीली जीन्स चुनें ताकि बैठने पर वह आपके पेट या जांघों को न काटे।
- **समय का निर्धारणः** अगर आपको टाइट जीन्स पहननी ही है, तो उसे केवल 2-3 घंटों के लिए किसी पार्टी या इवेंट में पहनें। घर आते ही ढीले और आरामदायक कपड़े (जैसे लोअर या पजामा) पहनें।
- **रात में परहेजः** सोते समय कभी भी टाइट कपड़े न पहनें। रात का समय शरीर की मरम्मत (REPAIR) का होता है, जिसके लिए रक्त संचार का सुचारू होना जरूरी है।
- **ऑफिस लाइफस्टाइलः** अगर आपका काम बैठने का है, तो ट्राउजर या ढीली फिटिंग वाली पैंट को प्राथमिकता दें।

खूबसूरती का 'सी' क्रेट

डाइट में विटामिन-C शामिल कर पाएं कुदरती निखार...

आज के आधुनिक दौर में प्रदूषण, बढ़ता तनाव और खान-पान की बिगड़ती आदतें हमारी सेहत के साथ-साथ हमारी त्वचा पर भी गहरा असर डाल रही हैं। बाजार में महंगे कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी पार्लर के महंगे ट्रीटमेंट और स्किन केयर प्रोडक्ट्स की भरमार है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स का स्पष्ट मानना है कि असली और स्थायी खूबसूरती 'बाहर' से नहीं, बल्कि 'अंदर' से आती है। विटामिन-C, जिसे विज्ञान की भाषा में 'एस्कॉर्बिक एसिड' कहा जाता है, एक ऐसा जादुई पोषक तत्व है जो आपकी त्वचा को उम्र के थपेड़ों से बचाकर उसे जवां, टाइट और चमकदार बनाए रखने की शक्ति रखता है...

विटामिन-Cः आपकी त्वचा का 'असली रक्षक'

न्यूट्रिशनिस्ट और 'वनडाइटटुडे' की फाउंडर डॉ. अनु अग्रवाल के अनुसार, विटामिन-C को 'एसेंशियल न्यूट्रिएंट' की श्रेणी में रखा गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारा शरीर इस विटामिन को खुद नहीं बना सकता और न ही इसे लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। इसलिए हमें इसे प्रतिदिन अपने भोजन के जरिए ही लेना पड़ता है। विटामिन-C का सबसे अहम काम त्वचा में 'कोलेजन' (Collagen) नामक प्रोटीन का निर्माण करना है। कोलेजन ही वह तत्व है जो त्वचा की परतों को मजबूती देता है, उसे ढीला होने से रोकता है और झुर्रियों को आने से थामता है। अक्सर लोग चमकती त्वचा के लिए बाजार से विटामिन-C के महंगे सप्लीमेंट या सीरम खरीदना पसंद करते हैं। हालांकि डॉ. अनु अग्रवाल का कहना है कि प्राकृतिक स्रोतों (फलों और सब्जियों) से मिलने वाला विटामिन-C शरीर में बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होता है। सप्लीमेंट्स केवल विशेष परिस्थिति में डॉक्टर की सलाह पर ही लेने चाहिए।

भोजन से मिलने वाला पोषण न केवल आपकी त्वचा को निखारता है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी (रोग प्रतिरोधक क्षमता) को भी बढ़ाता है, जिससे आप मौसमी बीमारियों से बचे रहते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, विटामिन-C की मात्रा व्यक्ति की आयु और लिंग पर निर्भर करती है। 19 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को प्रतिदिन लगभग 90 मिलीग्राम और महिलाओं को 75 मिलीग्राम विटामिन-C की आवश्यकता होती है। हालांकि, गर्भवती महिलाओं के लिए यह मात्रा 85 मिलीग्राम और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए 120 मिलीग्राम तक बढ़ जाती है। जो लोग स्मोकिंग (धूम्रपान) करते हैं, उनके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें सामान्य व्यक्ति से 35 मिलीग्राम अतिरिक्त विटामिन-C लेने की सलाह दी जाती है।

इन सस्ते और सुलभ खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं:

- **फलः** आंवला (विटामिन-C का राजा), अमरूद, संतरा, मौसमी, नींबू, कीवी, स्ट्रॉबेरी और पपीता।
- **सब्जियांः** लाल और पीली शिमला मिर्च, ब्रोकली, टमाटर और हरी पत्तेदार सब्जियां।

डॉ. अनु अग्रवाल बताती हैं कि सिर्फ विटामिन-C ही नहीं, बल्कि विटामिन-A, E, D और B-कॉम्प्लेक्स भी त्वचा के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन-A कोशिकाओं के नवीनीकरण में मदद करता है, जबकि विटामिन-E एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है। विटामिन-K आंखों के नीचे के काले घेरों को कम करने में मदद करता है। एक संतुलित आहार जिसमें ये सभी पोषक तत्व शामिल हों, आपकी त्वचा को उम्रभर जवां बनाए रख सकता है।

विटामिन-C की कमी के 9 बड़े 'स्किन डैमेज'

यदि आपके शरीर में इस जरूरी विटामिन की कमी है, तो आपकी त्वचा ये 9 संकेत देने लगेगी, जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए...

- **त्वचा का रूखापनः** स्किन का नैचुरल ग्लो खत्म होना और अत्यधिक ड्राई हो जाना।
- **देर से घाव भरनाः** छोटी-छोटी चोट या खरोंच के निशान ठीक होने में लंबा समय लगना।
- **समय से पहले बुढ़ापाः** चेहरे पर बारीक रेखाएं और झुर्रियां समय से पहले उभरना।
- **हाइपरपिग्मेंटेशनः** त्वचा पर काले या भूरे धब्बों (DARK SPOTS) का बढ़ना।
- **बेजान चेहराः** त्वचा का मुरझाया हुआ और थका हुआ नजर आना।
- **लाल चकत्तेः** चेहरे या शरीर की त्वचा पर छोटे-छोटे लाल दाने या सूजन दिखना।
- **कमजोर स्किन बैरियरः** धूप और प्रदूषण के संपर्क में आते ही स्किन का लाल हो जाना।
- **आंखों के नीचे डार्क सर्कल्सः** त्वचा की मोटाई कम होने से आंखों के नीचे घेरे दिखना।
- **कमजोर बालः** त्वचा के साथ-साथ बालों का बेजान होकर टूटना भी इसी कमी का संकेत है।

व्हाइट या ब्राउन शुगर, कौन-सी बेहतर

क्या डायबिटिक लोगों के लिए ब्राउन शुगर सेफ है, जानें दोनों के फायदे-नुकसान

एक सर्वे के मुताबिक, भारत की 80% से ज्यादा आबादी रोज सुबह चाय पीती है। यानी हमारे दिन की शुरुआत अक्सर एक चम्मच चीनी के साथ होती है, लेकिन कहानी सिर्फ चाय तक सीमित नहीं है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चीनी इतनी घुल-मिल गई है कि इसका एहसास ही नहीं होता है। बिस्किट और मिठाई से लेकर पैकेट बंद खाने-पीने की चीजों तक, हर जगह शुगर मिल ही जाती है।

हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया से लेकर बड़े-बड़े डॉक्टरों, किताबों और हेल्थ वेबसाइट्स तक, हर जगह चीनी के नुकसान पर खुलकर चर्चा होने लगी है। इसके कारण लोग व्हाइट शुगर से दूरी बनाने लगे हैं।

लेकिन हैरानी की बात ये है कि बहुत से लोग इसकी जगह ब्राउन शुगर को हेल्दी मानकर अपनी डाइट में शामिल करते हैं। जबकि ये सिर्फ मिथ है। रंग और स्वाद के फर्क के बावजूद ब्राउन और व्हाइट शुगर के न्यूट्रिशन और सेहत पर असर एक जैसे ही हैं। इसे लेकर कई गलतफहमियां फैली हुई हैं। ऐसे में सही जानकारी बेहद जरूरी है। तो चलिए, आज जरूरत की खबर में हम व्हाइट और ब्राउन शुगर के बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि-

व्हाइट और ब्राउन शुगर मूल रूप से एक ही सोर्स (गन्ना) से बनती हैं। दोनों के बीच असली अंतर उनकी प्रोसेसिंग और मोलासेस (गुड़ जैसा गाढ़ा शीरा) की मात्रा का होता है।

व्हाइट शुगर को पूरी तरह रिफाइन किया जाता है, जिसमें से मोलासेस निकाल दिया जाता है। इसी कारण इसका रंग सफेद और दाने सूखे होते हैं। मोलासेस निकालने के कारण इसमें एक खास तरह की सौंधी सुगंध भी नहीं होती है, जो कि ब्राउन शुगर में होती है। व्हाइट चीनी चाय, कॉफी और ज्यादातर रेसिपीज में आसानी से घुल जाती है।

वहीं जब रिफाइंड व्हाइट शुगर में दोबारा मोलासेस मिलाकर चीनी बनाई जाती है तो वह ब्राउन शुगर हो जाती है। मोलासेस की मात्रा 3% से लेकर 10% तक हो सकती है। यह ब्राउन शुगर की क्वालिटी और उसकी थिकनेस पर निर्भर करता है।

लाइट ब्राउन शुगर में मोलासेस कम होता है, जबकि डार्क ब्राउन शुगर में इसकी मात्रा ज्यादा होती है। इसी कारण ब्राउन शुगर नम, मुलायम होती है। इसमें हल्का कैरामेल (भुनी हुई मिठास) जैसा स्वाद आता है।

कुल मिलाकर कहने का आशय ये है कि सफेद चीनी और ब्राउन चीनी में फर्क सिर्फ स्वाद, नमी और रंग का है। दोनों के न्यूट्रिशन में कोई खास अंतर नहीं है। सेहत पर दोनों का प्रभाव भी बिल्कुल एक जैसा है।

राजधानी चौपाल

SELFIE POINT

अपनी सेल्फी हमें भेजें और अगली एडिशन में फीचर होने का मौका पाएं!

फोटो भेजने का तरीका

अपना कैमरा / मोबाइल से सेल्फी लें
WhatsApp खोलें
फोटो भेजें इस नंबर पर: 94169-26329
साथ में यह भी लिखें : नाम + गांव/शहर + तारीख

राजधानी चोपाल
WhatsApp channel

हमारे WhatsApp Channel से जुड़ें

- ताज़ा खबरें
- ब्राउंड रिपोर्ट
- स्पेशल अपडेट्स

बजट 2026 से बदलेगी तस्वीर...

इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और टेक्नोलॉजी को मिलेगी रफ्तार

इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बढ़ा निवेश

महंगाई नियंत्रण और रोजगार सृजन पर सरकार का जोर

आत्मनिर्भर भारत मिशन को मिला नया बजट बूस्ट

ग्रामीण भारत से लेकर स्मार्ट सिटी तक विकास का रोडमैप

मध्यम वर्ग और किसानों के लिए राहत के ऐलान

नई दिल्ली (राजधानी चौपाल) | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश करते हुए सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं, विकास रणनीति और भविष्य की योजनाओं को स्पष्ट रूप से सामने रखा। यह बजट ऐसे समय में आया है जब भारतीय अर्थव्यवस्था एक ओर तेज़ विकास दर बनाए रखने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर वैश्विक मंदी, भू-राजनीतिक तनाव, महंगाई और रोजगार सृजन जैसी चुनौतियों का सामना भी कर रही है।

बजट 2026 में सरकार ने तात्कालिक लोकलुभावन घोषणाओं से दूरी बनाते हुए लॉन्ग-टर्म ग्रोथ, हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और एक्सपोर्ट पर जोर दिया है। इस बजट का उद्देश्य देश की आर्थिक नींव को मजबूत करना और भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना बताया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार का लक्ष्य "समावेशी विकास, निवेश को प्रोत्साहन और आम नागरिक के जीवन को आसान बनाना" है। इसी सोच के तहत टैक्स स्ट्रक्चर, इम्पोर्ट ड्यूटी और सेक्टर-विशेष राहतों के जरिए अर्थव्यवस्था को दिशा देने की कोशिश की गई है।

बजट की बदली हुई भूमिका

बीते कुछ वर्षों में बजट का स्वरूप काफी बदल गया है। पहले जहां बजट के दिन ही रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम तय हो जाते थे, वहीं GST लागू होने के बाद अब अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें GST काउंसिल के दायरे में आती हैं। ऐसे में बजट का असर अब सीधे उपभोक्ता कीमतों पर कम और कस्टम ड्यूटी, टैक्स पॉलिसी और इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट फैसलों के जरिए ज्यादा देखने को मिलता है। बजट 2026 भी इसी बदले हुए आर्थिक ढांचे को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें सरकार ने उन क्षेत्रों पर फोकस किया है जो आने वाले वर्षों में देश की विकास दर को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

हेल्थकेयर सेक्टर को ऐतिहासिक राहत

बजट 2026 की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील घोषणा हेल्थ सेक्टर से जुड़ी रही। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 लाइफ-सेविंग दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा, 7 दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए विदेश से मंगवाई जाने वाली दवाओं और विशेष पोषण आहार (स्पेशल न्यूट्रिशन फूड) को भी टैक्स-फ्री कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि गंभीर बीमारियों का इलाज किसी भी कीमत पर आम नागरिक की पहुंच से बाहर नहीं होना चाहिए। ड्यूटी हटने से इन दवाओं की कीमतों में सीधी कमी आने की उम्मीद है, जिससे हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यह फैसला भारत में हेल्थकेयर को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

शेयर बाजार में ट्रेडिंग महंगी

डेरिवेटिव्स सेगमेंट में

- फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर STT 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत
- ऑप्शंस ट्रेडिंग पर STT 0.15 प्रतिशत
- इससे शॉर्ट-टर्म और एक्टिव ट्रेडर्स की लागत बढ़ेगी। सरकार का उद्देश्य अत्यधिक सट्टेबाज़ी पर नियंत्रण और राजस्व बढ़ाना बताया जा रहा है।

TCS और STT: संक्षिप्त समझ

- TCS (TAX COLLECTED AT SOURCE): यह एडवांस टैक्स होता है, जिसे बाद में इनकम टैक्स रिटर्न में समायोजित किया जा सकता है।
- STT (SECURITIES TRANSACTION TAX): यह हर सौदे पर लगने वाला सीधा टैक्स है, जो वापस नहीं मिलता।

मैन्युफैक्चरिंग और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा

- बजट 2026 में सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह भारत को केवल उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना चाहती है। इसी उद्देश्य से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में अहम बदलाव किए गए हैं।
- सरकार ने माइक्रोवेव ओवन बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है। इससे भारत में इन उत्पादों का निर्माण सस्ता होगा और कंपनियों को देश में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
- उद्योग जगत का मानना है कि इससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को भी कीमतों में राहत मिल सकती है।
- जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बजट 2026 में ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को खास महत्व दिया गया है। सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी बनाने वाली मशीनों पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया है।
- बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी समाप्त
- सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर भी ड्यूटी हटाई गई।

मुख्य घोषणाएं इस प्रकार हैं...

- सी-फूड एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी-फ्री इम्पोर्ट की सीमा 1% से बढ़ाकर 3 प्रतिशत
- लेदर और सिंथेटिक जूतों के साथ अब शू अपर्स के एक्सपोर्ट पर भी टैक्स छूट
- सरकार का मानना है कि इन कदमों से भारत का निर्यात बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा आएगी और इन श्रम-प्रधान क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- विदेश यात्रा करने वालों को राहत
- बजट 2026 में विदेश यात्रा करने वालों के लिए भी राहत की घोषणा की गई है। विदेश टूर पैकेज पर लगने वाला टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) अब घटाकर सीधा 2 प्रतिशत कर दिया गया है। पहले यह खर्च की राशि के आधार पर 5 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक था।
- इस फैसले से विदेश यात्रा की कुल लागत कम होगी और टूरिज्म सेक्टर को भी गति मिलने की उम्मीद है।
- एविएशन सेक्टर और MRO को बढ़ावा
- नागरिक उड्डयन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने एयरक्राफ्ट और उनके कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दी है।
- विदेश से निजी सामान मंगवाना हुआ सस्ता
- बजट 2026 में विदेश से निजी इस्तेमाल के लिए मंगवाए जाने वाले सामान पर टैक्स 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे आम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और अन्य निजी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ते में मंगा सकेंगे।
- **किन चीजों पर बढ़ा टैक्स का बोझ** : जहां एक ओर कई क्षेत्रों को राहत दी गई है, वहीं कुछ सेक्टर्स पर टैक्स बढ़ाकर सरकार ने राजस्व संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है।
- **शराब पर TCS बढ़ा** : शराब पर लगने वाला TCS 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि यह एडवांस टैक्स है और बाद में इनकम टैक्स रिटर्न में एडजस्ट हो सकता है।

बजट 2026: हरियाणा को क्या मिला, एक नजर...

सड़कों से अस्पताल तक, प्रदेश को मिला विकास का रोडमैप

चंडीगढ़ (राजधानी चौपाल) | केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश बजट 2026 का असर हरियाणा पर कई स्तरों पर देखने को मिलेगा। भले ही बजट में हरियाणा के लिए अलग से किसी परियोजना का नाम न लिया गया हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, स्वास्थ्य, ग्रीन एनर्जी और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी घोषणाओं से राज्य को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। औद्योगिक और कृषि प्रधान राज्य होने के कारण हरियाणा केंद्र की नीतियों का प्रमुख लाभार्थी बन सकता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क नेटवर्क को मजबूती : बजट 2026 में सड़क, हाईवे और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए पूंजीगत खर्च बढ़ाने का फैसला हरियाणा के लिए अहम माना जा रहा है। दिल्ली-एनसीआर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत और हिसार जैसे शहरों को भारतमाला, गति शक्ति और औद्योगिक कॉरिडोर योजनाओं के तहत बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

उद्योग और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा : बजट में मैन्युफैक्चरिंग और MSME सेक्टर को बढ़ावा देने की घोषणाओं से हरियाणा के ऑटोमोबाइल, ऑटो-कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल उद्योग को नई ऊर्जा मिलेगी। खास तौर पर EV बैटरी और ग्रीन एनर्जी से जुड़े कच्चे माल पर टैक्स छूट का फायदा गुरुग्राम-मानेसर औद्योगिक बेल्ट को मिलेगा। इससे नए निवेश, स्टार्ट-अप्स और तकनीकी नौकरियों के अवसर बढ़ने की संभावना है।

स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी राहत : बजट 2026 का सबसे मानवीय पहलू स्वास्थ्य सेक्टर से जुड़ा है। कैंसर की 17 जीवनरक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाने से हरियाणा के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। PGIMS रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बड़े सरकारी व निजी अस्पतालों में इलाज की लागत कम होने की उम्मीद है।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर : लॉजिस्टिक्स, कोल्ड-चेन और सप्लाई चेन सुधारों से हरियाणा के किसानों को फायदा मिलने की संभावना है। गेहूं, सरसों, सब्जी और डेयरी उत्पादों की बेहतर स्टोरेज और मार्केट तक पहुंच से किसानों की आय बढ़ सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

RNI No. HARHIN/25/A3341, प्रकाशक, मुद्रक स्वामी एवं संपादक राहुल कुमार द्वारा सूचना प्रिंटर्स 33एस मॉडल टाउन, हिसार से छपवाकर कार्यालय आदमपुर मंडी हिसार, (किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र हिसार न्यायालय होगा)।
संपादक : राहुल कुमार, फोन : 9306813001, e-mail : rajdhanichoupal@gmail.com, प्रकाशन स्थल : मकान संख्या : 114, शांति पार्क के पास, मंडी आदमपुर, हिसार (हरियाणा)